राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत-गुजरात,संस्करण बुधवार,३मार्च २०२१ वर्ष-४, अंक -३९ पृष्ठ-०८ मूल्य-०१रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पेट्रोल-डीजल जल्द हो सकता है सस्ता, टैक्स घटाने पर सरकार कर रही विचार: रिपोर्ट

- कोरोनावायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जिसके कारण बीते 12 महीनों में मोदी सरकार ने दो बार टैक्स बढ़ाया। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाकर सरकार टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहती थी। सरकार ने कच्चे तेल की की कम कीमतों का फायदा ग्राहकों को नहीं पहुंचाया।
- रॉयटर्स के मुताबिक अब वित्त मंत्रालय ने अब तेल की कीमतों पर टैक्स घटाने को लेकर विचार कर रहा है। इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने कुछ राज्यों, तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ चर्चा की है।

नई दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर सबसे ज्यादा असर डाला है। अब आम लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने पर विचार कर रही है। अभी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आम जनता पर बोझ कम करने के लिए सरकार टैक्स घटाने पर चर्चा कर रही है।

कच्चे तेल की कीमतें बीते 10 महीने में डबल हो चुकी है जिसने घरेलू बाजार यानी भारत में तेल की कीमतों पर असर डाला है। देश में टैक्स और ड्युटी के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम रिटेल में 60 फीसदी तक बढ़ जाते हैं। कच्चे तेल का भारत विश्व में तीसरा बड़ा ग्राहक देश है।

कोरोनावायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जिसके कारण बीते 12 महीनों में मोदी सरकार ने दो बार टैक्स बढ़ाया। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाकर सरकार टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना चाहती थी। सरकार ने कच्चे तेल की की कम कीमतों का फायदा ग्राहकों को नहीं पहुंचाया।

रॉयटर्स के मुताबिक अब वित्त मंत्रालय ने अब तेल की कीमतों पर टैक्स घटाने को लेकर विचार कर रहा है। इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने कुछ राज्यों, तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय चाहता है कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे सरकार की आमदनी पर भी असर ना पड़े और आम जनता को भी राहत दी जा सके।

पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रखने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ऐसे हल पर विचार कर रही है जिससे कीमतें स्थिर रखी जा सकें। मार्च के मध्य तक इस पर फैसला किया जा सकता है। टैक्स घटाने से पहले सरकार कीमतों को स्थिर करना चाहती है, जिससे भविष्य में कच्चे तेल की तीमतें बढ़ने पर टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव ना करना पड़े। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वह यह नहीं कह सकती कि ईंधन पर टैक्स कब कम होगा। लेकिन राज्यों और सरकार को टैक्स घटाने के लिए आपस में बात करनी होगी।

लगातार तीसरे दिन नहीं बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम

पेट्रोल और डीजल पर की कीमतें में आज लगातार तीसरे दिन नहीं बदली। तेल कंपनियों ने आज मंगलवार को भी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। राजधानी दिल्ली और मुंबई में इस वक्त पेट्रोल और डीजल इस वक्त अपने उच्चतम स्तर पर है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 91.17 रुपये जबकि डीजल का दाम 81.47 रुपये पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97.57 रुपये व डीजल की कीमत 88.60 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है।

हथियारों पर अधिक खर्च कर रहे हैं चीन और पाकिस्तान, भारत को रहना होगा ज्यादा सतर्क

नई दिल्ली। पहले भारत अधिकांश रक्षा उपकरणों का आयात करता था लेकिन अब हम निर्यातक की भूमिका में आ गए हैं। केंद्र ने आर्टिलरी गन तेजस टैंकों और मिसाइलों समेत अन्य रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए मंजूरी दी है। लक्ष्मी शंकर यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यह कहा है कि निजी क्षेत्र को रक्षा क्षेत्र में भी पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराने के लिए आगे आना होगा। वे रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश रक्षा क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बने यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अब रक्षा के पूंजीगत बजट में भी घरेलू खरीद के लिए एक हिस्सा रिजर्व कर दिया गया है। इसलिए निजी क्षेत्र को आगे आकर विश्व में अपना परचम लहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के पास हथियार एवं सैन्य उपकरण बनाने का सदियों पुराना अनुभव है, जिसका लाभ लिया जाना चाहिए। इससे पहले बेंगलुरू में एयर इंडिया शो के दौरान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को भारत मिसाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली सहित विभिन्न प्रकार की हथियार प्रणालियों की आपूर्ति करने को तैयार है। इससे पहले केवल आकाश मिसाइल के निर्यात को मंजूरी प्रदान की गई थी, परंतु अब हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग और क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भी निर्यात के लिए तैयार हैं। आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है और कम दूरी की हवाई सुरक्षा प्रदान करती है। आने वाले समय में अस्त्र मिसाइल को भी लड़ाकू विमानों के साथ एकीकृत किया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल को जहाजों, मोबाइल लांचर, पनडुब्बियों एवं एयरक्राफ्ट से छोड़ा जा सकता है।

विश्व में तेजी से बढ़ रहे हैं हार्ट फेल के मामले, भारत पहुंचा दूसरे नंबर पर

नई दिल्ली। दुनियाभर में हार्ट फेल के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया में हार्ट फेल से होने वाली मौत के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। यह खुलासा यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में प्रकाशित शोध में हुआ है। शोध के मुताबिक, 2017 में हार्ट फेल के केसों की संख्या 64.3 मिलियन थी, जिनमें 29.5 मिलियन पुरुष थे, जबकि महिलाओं की संख्या 34.8 मिलियन थी। रिपोर्ट के अनुसार, 1990 से 2017 के बीच हार्ट फेल के मामलों में 91.9 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। अध्ययन के अनुसार, 1990 से 2017 के दौरान हार्ट फेल के मामले करीब-करीब दोगुने हो गए हैं। यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में प्रकाशित शोध के अनुसार, हार्ट फेल के मामले 70 से 74 साल के पुरुषों में अधिक है। वहीं, 75-79 साल की महिलाओं में हार्ट फेल के मामले ज्यादा हैं। प्रमुख बात यह है कि 70 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हार्ट फेल के मामले अधिक हैं। रिपोर्ट में बड़ी बात यह है कि हार्ट फेल के मामले 1990-2017 के दौरान चीन और भारत में सबसे अधिक बढ़े हैं। चीन में हार्ट फेल के मामले 29.9 फीसद बढ़े हैं, वहीं भारत में 16 फीसद बढ़े हैं। यानी सीधे तौर पर कहें तो यह एशिया में तेजी से बढ़ रहा है। भारत और चीन जैसे देशों में वायु प्रदूषण भी कार्डियोवास्कलुर रोग और सांस की बीमारी जैसे रोगों का प्रमुख कारण है। दुनियाभर में सबसे अधिक मामले इस्केमिक हार्ट रोग के होते हैं। ये कुल मामलों का 26.5 फीसद होते हैं। जबकि हाइपरसेंसिटिव हार्ट रोग और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कुल मामलों का क्रमश- 26.2 और 23.4 प्रतिशत होते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, इस्केमिक हार्ट रोग, ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और एल्कोहलिक कार्डियोपैथी पुरुषों में अधिक होती है, जबकि हाइपरसेंसिटिव हार्ट रोग और रयूमेटिक हार्ट रोग महिलाओं में अधिक होते हैं।

बिहार के शहरों को मिलेगी विरासत कचरे से मुक्ति, राजधानी से होगी शुरुआत

पटना। बिहार के शहरों को कचरे के उन ऊंचे-ऊंचे ढेरों से मुक्ति मिलेगी। यह कूड़े के वे ढेर हैं, जो सालों से बढ़-बढ़कर पहाड़ बन चुके हैं। राजधानी पटना से इसकी शुरुआत की जा रही है। राज्य में सबसे पहले विरासत कचरे (लीगेसी वेस्ट) के ट्रीटमेंट का काम पटना से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पटना के बाद मुजफ्फरपुर में विरासत कचरे के ट्रीटमेंट का काम शुरू होगा।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) विरासत कचरे को लेकर बेहद गंभीर है। ट्रिब्यूनल का आदेश है कि सभी शहरी निकाय अपने यहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं। यह नियमावली कचरा और मलबा प्रबंधन से जुड़ी है। राज्य के शहरी निकायों की बात करें तो इस दिशा में काम तो शुरू हुआ है मगर मंजिल अभी काफी दूर है। किसी भी शहर में कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था न होने के कारण कूड़े के बड़े-बड़े ढेर लग गए हैं। वर्षों या यूं कहें कि दशकों से लग रहे इन ढेरों को

विरासत कचरा नाम दिया गया है। लीगेसी वेस्ट के इन ढेरों के कारण जल और वायु दोनों तरह का प्रदूषण फैल रहा है। लंबे समय से सड़ रहे कचरे ने भूगर्भ जल तक को प्रभावित कर दिया है। इसके अलावा उसमें जहरीली गैस बनने के कारण अक्सर कचरे के यह ढेर सुलगते रहते हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देश पर पटना ने लीगेसी वेस्ट के उपचार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिर मुजफ्फरपुर और बाकी शहरों में भी इसे किया जाएगा।

बेरिया में लगेगा प्लांट

पटना नगर निगम की ओर से विरासत कचरे के बायो मायनिंग विधि से उपचार के लिए एजेंसी चयन को आवेदन मांगे गए हैं। बेरिया में 300 टन क्षमता का प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्लांट स्थापित करने के साथ ही उसके ऑपरेशन और मेंटीनेंस भी एजेंसी को करनी होगी। इसके अलावा वहां कंपोस्ट बनाने का प्लांट भी लगेगा। इसके लिए 10 मार्च को प्री-बिड मीटिंग आयोजित की गई है।

बिहार में अब कांट्रेक्ट बेस सरकारी नौकरी चाहिए तो सौंपना होगा ये अहम दस्तावेज, आदेश जारी

पटना। बिहार में राज्य सरकार के अधीन कांट्रेक्ट बेस सरकारी नौकरी चाहिए तो कैंडिडेट्स को ये अहम दस्तावेज जमा करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है। दरअसल बिहार में संविदा आधारित नियोजन के लिए अब चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए जरूरी जानकारी खुद अनुशंसित उम्मीदवार को देनी होगी जिनका नियोजन होना है। इस दौरान कोई उम्मीदवार यदि अपने ऊपर दायर आपराधिक मामले को छुपाता है तो उसे कदाचार माना जाएगा।

नियमित नियुक्ति में पहले से प्रावधान

बिहार सरकार में स्वच्छ छवि के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति हो इसके लिए साल 2006 में ही नौकरी हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन का प्रावधान है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया है जिसमें जरूरी सूचनाएं अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं भरी जाती हैं। संविदा आधारित विभिन्न पदों पर नियोजन के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत सत्यापन कराने का मामला सरकार के पास विचाराधीन था। अब इसे लागू कर दिया गया है।

जिलाधिकारी भेजेंगे पुलिस को

संविदा पर नियोजन के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को सत्यापन का फॉर्म खुद भरना होगा। इसमें उन्हें पूर्ण एवं सही सूचनाएं देनी होंगी। अभ्यर्थी को अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामले की सूचना सही-सही अंकित करनी होगी। ऐसी किसी सूचना को छुपाया जाता है तो उसे संबंधित कर्मी का कदाचार माना जाएगा। फॉर्म को सत्यापन के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से पुलिस को भेजा जाएगा।

आंदोलनकारियों को अब संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर भरना होगा एक लाख तक जुर्माना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आंदोलनकारियों को अब सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना भारी पड़ेगा। इसकी पुष्टि होने पर 5000 से एक लाख रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। विधानसभा में सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति विरूपण निवारण विधेयक-2021 पास हो गया। सपा द्वारा इसे प्रवर समिति को भेजने संबंधी प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा सरकारी और निजी संपत्तियों की रक्षा करना है। इसीलिए यह विधेयक लगाया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद प्रदेश में राजनीतिक जुलूसों, प्रदर्शन, हड़ताल, कामबंदी और आंदोलन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाना भारी पड़ेगा। केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, निगम, राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित संस्थाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा। आंदोलन के दौरान सौंदर्य नष्ट करने, तोड़फोड़ करने, किसी तरह खराब करना या क्षति पहुंचाने, उसमें स्याही, खड़िया, पेंट या किसी अन्य सामग्री से चिह्नित करने से होने वाले नुकसान को

इस कानून के दायरे में रखा गया है। निजी संपत्ति को भी इसके दायरे में रखा गया है। नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने संबंधी प्रस्ताव पर कहा कि इसके बहाने सरकार आंदोलन पर रोक लगाना चाहती है। बसपा के लालजी वर्मा ने कहा कि सरकार विधेयक बहुत तेजी से लाती है और बहुत तेजी से वापस भी लेती है।

दो जिलों में संयुक्त व उप पुलिस आयुक्त को गुंडा एक्ट में सुनवाई का अधिकार

राज्य सरकार ने लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में गुंडा एक्ट के तहत सुनवाई का अधिकार संयुक्त पुलिस आयुक्त और उप पुलिस आयुक्त को दे दिया है। इसके साथ ही इन दोनों जिलों में मंडलायुक्त के स्थान पर पुलिस आयुक्त को अपील सुनने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए सोमवार को विधानसभा में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी गई है।

पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के बाद अब CNG और PNG भी हुई महंगी

नई दिल्ली। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के बाद अब सीएनजी भी महंगी हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कहा है कि आज सुबह छह बजे से दिल्ली में सीएनजी अब आपको 42.70 रुपए की जगह 43.40 रुपए प्रति किलो मिलेगी। वहीं, पीएनजी की कीमत 28.41 रुपए मिलेगी। आपको बता दें कि पीएनजी की कीमत में 0.91 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गाजियाबाद में अब पीएनजी 28.36 रुपए प्रति किलो मिलेगी। आपको बता दें कि रसोई गैस यानी एलपीजी में सोमवार को प्रति सिलेंडर 25 रुपये की और वृद्धि हुई थी। यह वृद्धि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिए जाने वाले सब्सिडी वाले सिलेंडर सहित सभी श्रेणियों में हुई। एक माह में रसोई गैस सिलेंडर के दाम चौथी बार बढ़े हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों के मूल्य आंकड़ों से पता चलता है कि फरवरी से अब तक 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर के दाम 125 रुपये बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही विमान ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों में भी को 6.5 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में तेजी आ रही है, जिससे विमान ईंधन महंगा हुआ है। दिल्ली में अब 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर का दाम 794 रुपये से बढ़कर 819 रुपये हो गया है। यह वृद्धि सभी श्रेणियों...सब्सिडी वाले और बिना सब्सिडी वाले दोनों सिलेंडरों में की गई है। देशभर में एलपीजी का दाम एक ही होता है। सरकार कुछ चुनिंदा ग्राहकों को इस पर सब्सिडी देती है। हालांकि, पिछले कुछ साल के दौरान

महानगरों और बड़े शहरों में कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद सब्सिडी बंद हो गई है। दिल्ली में उपभोक्ताओं को एलपीजी पर कोई सब्सिडी नहीं मिलती। सभी उपभोक्ताओं के लिए अब रसोई गैस सिलेंडर का दाम 819 रुपये हो गया है। पेट्रोलियम कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेंडर पर कुछ सब्सिडी दी जाती है। ढुलाई भाड़े की भरपाई करने के लिए यह सब्सिडी दी जाती है। इससे पहले चार फरवरी को एलपीजी के दाम 25 रुपये प्रति सिलेंडर और 15 फरवरी को 50 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए थे। 25 फरवरी को एलपीजी के दाम 25 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए थे। दिसंबर से रसोई गैस सिलेंडर लगातार महंगा हो रहा है। इस दौरान रसोई गैस की कीमतों में 175 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

क्या हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

हालांकि, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन कोई वृद्धि नहीं की गई। दिल्ली में पेट्रोल 91.17 रुपये और मुंबई में 97.57 रुपये प्रति लीटर है। दिल्ली में डीजल 81.47 रुपये और मुंबई में 88.60 रुपये प्रति लीटर पर है। पिछले महीने राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया था। ये दोनों राज्य ईंधन पर सबसे अधिक मूल्य वर्धित कर (वैट) लेते हैं। मुंबई में शनिवार को ब्रांडेड/प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपये को पार कर गया। इस समय यह 100.35 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

ऊर्जा तंत्र में सेंध

अमेरिका से आई एक रिपोर्ट ने चीन के प्रति भारत को आगाह किया है, तो कोई आश्चर्य नहीं। साइबरस्पेस कंपनी, रिकॉर्डेड फ्यूचर ने भारत सरकार को चीन से जुड़े खतरे की सूचना दी है। रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि चीन का एक साइबर समूह रेड इको मुंबई में बिजली फेल होने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। यह आरोप लगाते हुए रिकॉर्डेड फ्यूचर ने ठोस प्रमाण तो नहीं पेश किए हैं, पर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के जरिए यह समझाने की कोशिश की है कि चीन खतरा बन सकता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पावर ग्रिड नेटवर्क का संचालन साइबर आधारित होता जा रहा है। जिस इंटरनेट प्रोग्राम के जरिए पावर ग्रिड को संभाला जाता है, अगर उसमें कोई देश घुसपैठ कर ले, तो वाकई किसी भी देश में बिजली की व्यवस्था को बाधित कर सकता है। अमेरिकी रिपोर्ट ने बताया है कि 12 अक्तूबर, 2020 को मुंबई में बिजली व्यवस्था ठप हो गई थी, यह कारस्तानी चीन के हैकरों की हो सकती है। इस रिपोर्ट के बाद भारत सरकार को पूरी गंभीरता से इस कथित घुसपैठ की जांच करनी चाहिए। संभव है, यह जांच पहले से ही जारी हो और भारतीय साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस तकनीकी आपदा का इलाज खोज लिया हो। वाकई यह चिंता की बात है, अगर चीन भारतीय बिजली व्यवस्था में घुसपैठ में सक्षम हो चुका है। क्या भारत में ऐसा करने में सक्षम है? विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसी ही घुसपैठ रूस ने अमेरिकी पावर ग्रिड में की थी, लेकिन तब अमेरिकी विशेषज्ञों ने भी रूसी पावर ग्रिड में सेंध मारकर रूसियों को सचेत कर दिया था। भारत को आगाह करते हुए रिपोर्ट ने यह स्पष्ट संकेत कर दिया है कि साइबर सेंध से बचने में वही देश कामयाब होगा, जो साइबर सेंध मारने की क्षमता रखेगा। भारत को ऐसे साइबर युद्ध से बचने में पूरी तरह सक्षम होना चाहिए और इसके साथ ही उसको निशाना बनाने वाले दुश्मनों को भी पता होना चाहिए कि सेंधमारी करके वह भी नहीं बचेंगे। दुश्मन आप से उसी हथियार से लड़ना चाहता है, जिसमें वह आपको कमजोर मानता है। हमें देखना होगा कि साइबर सुरक्षा के मामले में अगर चीन हमें कमजोर मान रहा है, तो हम अपनी कमजोरी कैसे दूर करेंगे। एक सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका इन दिनों भारत के लिए अतिरिक्त रूप से सचेत है। अमेरिका के भी अनेक पहलू हैं, वहां अनेक तरह की संस्थाएं हैं, जो अपने-अपने ढंग से विश्लेषण करती रहती हैं। हमें अपने स्तर पर भला-बुरा सोचते हुए चलना है। चीन और अमेरिका के बीच बहुत भौगोलिक दूरी है, लेकिन चीन हमारा पड़ोसी है। हम न तो अत्यधिक उदार हो सकते हैं और न अत्यधिक आक्रामक। हमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक संतुलन बनाकर चलना होगा। अपनी बिजली व्यवस्था को ही नहीं, अपने पूरे तंत्र को चाक-चौबंद बनाना होगा। प्रौद्योगिकी के स्तर पर किसी भी तरह की सेंध की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। बिजली, पानी की आपूर्ति ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह की सार्वजनिक सेवा भी साइबर हमले में बाधित नहीं होनी चाहिए। दुनिया के तमाम विकसित देश अपनी-अपनी साइबर सुरक्षा मजबूत करने में लगे हैं, चीन तो खासतौर पर सक्रिय है। हमें मानकर चलना चाहिए कि साइबर मैदान में युद्ध अब निरंतर जारी रहेगा। लुटने से वही बचेगा, जिसके ताले अकाट्य होंगे।

आज के ट्वीट

मुहर

गुजरात के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र ने सर्वसम्मति से विकास पर मुहर लगाई है। सरकार के जनहित के कार्यों ने जहां लोगों के दिलों में जगह बनाई है, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत रंग लाई है। हमारी पार्टी गुजरात के सभी भाई-बहनों की प्रगति और राज्य की उन्नति के लिए काम करती रहेगी। -- पीएम

जैव विविधता पर मंडराता खतरा

विश्व वन्यजीव दिवस (3 मार्च) पर विशेष/ योगेश कुमार गोयल

जैव विविधता की समृद्धि ही धरती को रहने तथा जीवन यापन के योग्य बनाती है किन्तु विडम्बना है कि निरन्तर बढ़ते प्रदूषण रूपी राक्षस वातावरण पर इतना खतरनाक प्रभाव डाल रहा है कि जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां धीरे-धीरे लुप्त हो रही हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसम्बर 2013 को अपने 68वें सत्र में 3 मार्च के दिन को 'विश्व वन्यजीव दिवस' के रूप में अपनाए जाने की घोषणा की। अगर भारत में कुछ जीव-जंतुओं की प्रजातियों पर मंडराते खतरों की बात करें तो जैव विविधता पर दिसम्बर 2018 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीबीडी) में पेश की गई छठी राष्ट्रीय रिपोर्ट से पता चला था कि अंतर्राष्ट्रीय 'रेड लिस्ट' की गंभीर रूप से लुप्तप्रायः और संकटग्रस्त श्रेणियों में भारतीय जीव प्रजातियों की सूची वर्षों से बढ़ रही है। इस सूची में शामिल प्रजातियों की संख्या में वृद्धि जैव विविधता तथा वन्य आवासों पर गंभीर तनाव का संकेत है। भारत में इस समय नौ सौ से भी अधिक दुर्लभ प्रजातियां खतरे में बताई जा रही हैं। यही नहीं, विश्व धरोहर को गंवाने वाले देशों की सूची में दुनियाभर में भारत का चीन के बाद सातवां स्थान है। भारत का समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र करीब 20444 जीव प्रजातियों के समुदाय की मेजबानी करता है, जिनमें से 1180 प्रजातियों को संकटग्रस्त तथा तत्काल संरक्षण के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अगर देश में प्रमुख रूप से लुप्त होती कुछेक जीव-जंतुओं की प्रजातियों की बात करें तो कश्मीर में पाए जाने वाले हांगलू की संख्या सिर्फ दो सौ के आसपास रह गई है, जिनमें से करीब 110 दाचीगाम नेशनल पार्क में हैं। इसी प्रकार आमतौर पर दलदली क्षेत्रों में पाई जाने वाली बारहसिंगा हिरण की प्रजाति अब मध्य भारत के कुछ वनों तक ही सीमित रह गई है। वर्ष 1987 के बाद से मालाबार गंधबिलाव नहीं देखा गया है। हालांकि माना जाता है कि इनकी संख्या पश्चिमी घाट में फिलहाल दो सौ के करीब बची है। दक्षिण अंडमान के माउंट हैरियट में पाया जाने वाला दुनिया का सबसे छोटा स्तनपायी सफेद दांत वाला छछूंदर लुप्त होने के कगार पर है। एशियाई शेर भी गुजरात के गिर वनों तक ही सीमित हैं। देश में हर साल बड़ी संख्या में बाघ मर रहे हैं, हाथी कई बार ट्रेनों से टकराकर मौत के मुंह में समा रहे हैं, इनमें से कईयों को वन्य तस्कर मार डालते हैं। कभी गांवों या शहरों में बाघ घुस आता है तो कभी तेंदुआ और घंटों-घंटों या कई-कई दिनों तक दहशत का माहौल बन जाता है। यह सब वन क्षेत्रों के घटने और विकास परियोजनाओं के चलते वन्य जीवों के आश्रय स्थलों में बढ़ती मानवीय घुसपैठ का ही परिणाम है कि वन्य जीवों तथा मनुष्यों का टकराव लगातार बढ़ रहा है और वन्य प्राणी अभयारण्यों की सीमा पार कर बाघ, तेंदुए इत्यादि वन्य जीव अब अक्सर बेघर होकर भोजन की तलाश में शहरों का रुख करने लगे हैं, जो कभी खेतों में लहलहाती फसलों को तहस-नहस कर देते हैं तो कभी इंसानों पर जानलेवा हमले कर देते हैं। 'इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर' (आईयूसीएन) के मुताबिक भारत में पौधों की करीब 45 हजार प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से भी 1336 प्रजातियों पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इसी प्रकार फूलों की पाई जाने वाली 15 हजार प्रजातियों में से डेढ़ हजार प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदूषण तथा स्मॉग भरे वातावरण में कीड़े-मकोड़े सुस्त पड़ जाते हैं। प्रदूषण का जहर अब मधुमक्खियों तथा सिल्क वर्म जैसे जीवों के शरीर में भी पहुंच रहा है। रंग-बिरंगी तितलियों को भी इससे काफी नुकसान हो रहा है। यही नहीं, अत्यधिक प्रदूषित स्थानों पर तो पेड़-पौधों पर भी इसका इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि हवा में सल्फर डाईऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ओजोन की अधिक मात्रा के चलते पेड़-पौधों की पत्तियां भी जल्दी टूट जाती हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि अगर इस ओर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में स्थितियां इतनी खतरनाक हो जाएंगी कि धरती से पेड़-पौधों तथा जीव-जंतुओं की कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। पृथ्वी पर पेड़ों की संख्या घटने से अनेक जानवरों और पक्षियों से उनके आशियाने छिन रहे हैं, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ रहा है। वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत में पहला कानून 'वाइल्ड एलीकेंट प्रोटेक्शन एक्ट' ब्रिटिश शासनकाल में 1872 में बनाया गया था। 1927 में ब्रिटिश शासनकाल मं ही 'भारतीय वन अधिनियम' बनाकर वन्य जीवों का शिकार तथा वनों की अवैध कटाई को अपराध की श्रेणी में रखते हुए दंड का प्रावधान किया गया। 1956 में एकबार फिर 'भारतीय वन अधिनियम' पारित किया गया और वन्य जीवों के बिगड़ते हालातों में सुधार के लिए 1983 में 'राष्ट्रीय वन्य जीव योजना' की शुरुआत की गई, जिसके तहत कई नेशनल पार्क और वन्य प्राणी अभयारण्य बनाए गए। हालांकि नेशनल पार्क बनाने का सिलसिला ब्रिटिश काल में ही शुरू हो गया था, जब सबसे पहला नेशनल पार्क 1905 में असम में बनाया गया था और उसके बाद दूसरा नेशनल पार्क 'जिम कार्बेट पार्क' 1936 में बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए उत्तराखण्ड में बनाया गया था लेकिन आज नेशनल पार्कों की संख्या बढ़कर 103 हो गई है और देश में कुल 530 वन्य जीव अभयारण्य भी हैं, जिनमें 13 राज्यों में 18 बाघ अभयारण्य भी स्थापित किए गए हैं। आजादी के बाद से देश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें 'कस्तूरी मृग परियोजना 1970', 'प्रोजेक्ट हुंगल 1970', 'गिर सिंह परियोजना 1972', 'बाघ परियोजना 1973', 'कछुआ संरक्षण परियोजना 1975', 'गैंडा परियोजना 1987', 'हाथी परियोजना 1992', 'गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006', 'हिम तेंदुआ परियोजना 2009' इत्यादि शामिल हैं। इस तरह की कई परियोजनाएं शुरू किए जाने के

बावजूद शेर, बाघ, हाथी, गैंडे इत्यादि अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत फिलहाल जैव विविधता पर करीब दो अरब डॉलर खर्च कर रहा है और इसे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही परियोजनाओं की सफलता ही माना जाना चाहिए कि जहां 2006 में देश में व्यस्क बाघों की संख्या 1411 थी, वह 2010 में बढ़कर 1706, 2014 में 2226 और 2018 में 2967 हो गई। हालांकि बाघों की बढ़ी संख्या का यह आंकड़ा अभी संतोषजनक नहीं है क्योंकि इसी देश में कभी बाघों की संख्या करीब 40 हजार हुआ करती थी। सरकारी योजनाओं की सफलता का ही असर है कि आईयूसीन द्वारा शेर जैसी पूंछवाले बंदरों की संख्या बढ़ने के कारण इन्हें 25 लुप्तप्रायः जानवरों की सूची से हटा दिया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 2011 में भारत में जानवरों की 193 नई प्रजातियां भी पाई गई। माना कि धरती पर मानव की बढ़ती जरूरतों और सुविधाओं की पूर्ति के लिए विकास आवश्यक है लेकिन यह हमें ही तय करना होगा कि विकास के इस दौर में पर्यावरण तथा जीव-जंतुओं के लिए खतरा उत्पन्न न हो। अगर विकास के नाम पर वनों की बड़े पैमाने पर कटाई के साथ-साथ जीव-जंतुओं तथा पक्षियों से उनके आवास छीने जाते रहे और ये प्रजातियां धीरे-धीरे धरती से एक-एक कर लुप्त होती गई तो भविष्य में उससे उत्पन्न होने वाली भयावह समस्याओं और खतरों का सामना हमें ही करना होगा। बढ़ती आबादी तथा जंगलों के तेजी से होते शहरीकरण ने मनुष्य को इस कदर स्वार्थी बना दिया है कि वह प्रकृति प्रदत्त उन साधनों के स्रोतों को भूल चुका है, जिनके बिना उसका जीवन ही असंभव है। आज अगर खेतों में कीटों को मारकर खाने वाले चिड़िया, मोर, तीतर, बटेर, कौआ, बाज, गिद्ध जैसे किसानों के हितैषी माने जाने वाले पक्षी भी तेजी से लुप्त होने के कगार हैं तो हमें आसानी से समझ लेना चाहिए कि हम भयावह खतरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमें अब समय रहते सचेत हो जाना चाहिए। हमें अब भली-भांति समझ लेना होगा कि पृथ्वी पर जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम धरती की पर्यावरण संबंधित स्थिति के तालमेल को बनाए रखें।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

ज्ञान गंगा

तीन दुख

श्रीराम शर्मा आचार्य/ समस्त दुःखों का कारण है-अज्ञान, अशक्ति व अभाव। जो इन तीनों को जिस सीमा तक अपने से दूर करने में समर्थ होगा, वह उतना ही सुखी बन सकेगा। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वह तत्वज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा-सीधा सोचता और करता है। तद्नुरूप उलझनों में फंसता जाता है और दुःखी बनता है। स्वार्थ, लोभ, अहंकार और क्रोध की भावनाएं मनुष्य को कर्त्तव्यच्युत करती हैं और वह दूरदर्शिता को छोड़कर क्षणिक लाभ वाले बातें ही सोचता है तथा वैसे ही करता है। फलस्वरूप उसके विचार और कार्य पापमय होने लगते हैं। पापों का निश्चित परिणाम दुःख ही है। अज्ञान के कारण वह अपने और दूसरे सांसारिक गतिविधियों के मूल हेतुओं को नहीं समझ पाता और असंभव आशाएं रखता है। इस उल्टे दृष्टिकोण के कारण साधारण सी बातें उसे दुःखमय दिखाई देती हैं जिसके कारण वह रोता-चिल्लाता रहता है। अपने करीबियों की मृत्यु, साथियों की भिन्न रुचि, परिस्थितियों का उतार-चढ़ाव स्वाभाविक है। पर अज्ञानी सोचता है कि मैं जो चाहता हूं, वही होता रहे। अज्ञान के कारण भूलें भी अनेक प्रकार की होती हैं। समीपस्थ सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, यह भी दुःख का हेतु है। अशक्ति का अर्थ है-निर्बलता। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलता के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक अधिकारों का भार अपने कंधों पर उठाने में समर्थ नहीं होता। फलस्वरूप उसे वंचित रहना पड़ता है। शरीर को बीमारी ने घेर रखा हो तो स्वादिष्ट भोजन, मधुर संगीत आदि निर्थक हैं। धन-दौलत का कोई कहने लायक सुख उसे नहीं मिल सकता। बौद्धिक निर्बलता हो तो साहित्य, मनन, चिंतन का रस प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मिक निर्बलता हो तो सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आनंद दुर्लभ है। सर्दी जो बलवानों को बल-बुद्धि प्रदान करती है, रसिकों को रस देती है, वह कमजोरों को निमोनिया, गठिया आदि का कारण बन जाती है। जो तत्व निर्बलों के लिए प्राणघातक हैं, वे ही बलवानों को सहायक सिद्ध होते हैं। कमजोर को सताने और मिटाने के लिए अनेकों तथ्य प्रकट हो जाते हैं। अभावजन्य दुःख है-पदाथरे का अभाव। अन्न, वस्त्र, मकान, औषधि आदि के अभाव में विविध प्रकार की पीड़ाएं, कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं। उचित आवश्यकताओं को कुचलकर, मन मारकर बैठना पड़ता है और जीवन के महत्त्वपूर्ण क्षणों को मिट्टी के मोल नष्ट करना पड़ता है। योग्य और समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव में लुंज-पुंज अनुभव करते हैं और दुःख उठाते हैं। तीनों प्रकार के दुःखों के कारणों को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

एमएसपी से तिलहन में आत्मनिर्भरता

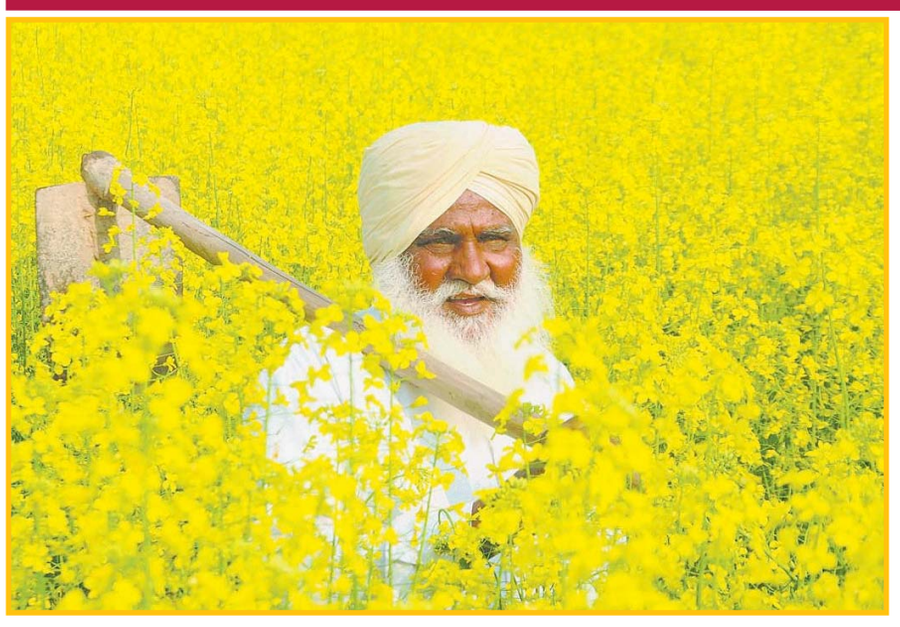

शेर सिंह सांगवान

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा 1970 से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं और चावल की असीमित खरीद नीति; अनाज में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए किसानों हेतु एक निर्णायक प्रोत्साहन साबित हुई है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं की एमएसपी पर खरीद पिछले 50 वर्षों से हो रही है तथा मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश पिछले 10 वर्षों में शामिल हुए हैं, जिससे उनके गेहूं उत्पादन में तेजी आई है। इसी तरह, चावल की खरीद मुख्य रूप से पंजाब, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में की की जा रही है, लेकिन हाल के वर्षों में, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा जैसे अन्य राज्य भी इसमें शामिल हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसका उत्पादन तेजी से हुआ है। निरंतर एमएसपी पर खरीद के कारण चावल और गेहूं का वर्तमान स्टॉक उनके आवश्यक बफर के दोगुने से अधिक है, जबकि हम लगभग एक लाख करोड़ रुपये के दाल और तिलहन आयात कर रहे है। भारत सरकार ने खरीफ 2017 से दालों और तिलहन की खरीद भी एक अभूतपूर्व मात्रा में की है। यह खरीद उनकी एमएसपी पर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत नेफेड के माध्यम से राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में की गई है। इनमें से अधिकांश राज्य गेहूं और चावल की खरीद के लाभार्थी नहीं रहे हैं। इन राज्यों के किसानों ने इन फसलों के तहत रकबा बढ़ाया है। पिछले कुछ वर्षों में दालों की एमएसपी पर बढ़ी हुई खरीद के परिणामस्वरूप ही 2018-19 के बाद से उनका आयात नगण्य है, जो 2016-17 में लगभग 6 मिलियन टन था। लेकिन तिलहन उत्पादन में अब तक वृद्धि पर्याप्त नहीं है क्योंकि अभी भी हम लगभग 15 मिलियन टन वनस्पति तेल और बीज का आयात कर रहे हैं, जिसकी लागत का लगभग 70000 करोड़ रुपये है। अभी भी पंजाब, हरियाणा और यूपी के गेहूं उत्पादक राज्यों में किसान तिलहन के तहत कम क्षेत्र आवंटित कर रहे हैं, हालांकि, सरसों से उनकी आय गेहूं से अधिक है। उदाहरण के लिए, दो साल पहले, गेहूं उत्पादन में अग्रणी कैथल जिले के एक किसान ने बताया कि वे गेहूं की तुलना में सरसों से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एमएसपी पर सरसों खरीद की अनिश्चितता और उसकी कीमतों में अधिक अस्थिरता उन्हें वापस मोड़ रही है। उल्लेखनीय है कि कैथल जिले में हरियाणा में सरसों की सबसे अधिक पैदावार 11 क्विंटल प्रति एकड़ है और वर्ष 2021 में एमएसपी पर इसका सकल मूल्य रु. 51150 है, इसकी तुलना में गेहूं से 20 क्विंटल औसत उपज पर 39500 रुपये है। इसके अलावा गेहूं के मुक़ाबले सरसों के उत्पादन की लागत कम होगी। पंजाब के कुछ जिलों में 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक की उपज की सूचना दी गई है। यदि एमएसपी पर सरसों की खरीद को असीमित कर दिया जाता है तो उसका मूल्य जोखिम शून्य हो जायेगा, तब कई किसान अधिक आय के लिए गेहूं से सरसों के उत्पादन में बदलाव करेंगे। स्मरण रहे कि वर्तमान में सरसों की एमएसपी पर खरीद, उत्पादन का 25 प्रतिशत या 25 क्विंटल प्रति किसान है जब कि गेहूं की खरीद असीमित है। एमएसपी पर खरीद सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा के लिए अनाज स्टॉक बढ़ाने के लिए एफसीआई द्वारा शुरू की गई थी। एफसीआई का लाभ कमाने का कोई मकसद नहीं है यही कारण है कि आज उस पर लगभग 3 लाख करोड़ की देनदारी है। यह सोचा गया था कि नेफेड द्वारा तिलहन और दालों की 25 प्रतिशत खरीद के बाद, बाजार मूल्य में वृद्धि होगी परंतु 2018-19 में 8 राज्यों के हमारे अध्ययन के दौरान पता चला कि ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए, अनाज और दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के बाद, भारत सरकार को तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और अपने आयात में प्रति वर्ष लगभग एक लाख करोड़ रुपये बचाने के लिए कुछ वर्षों के लिए 100 प्रतिशत तिलहन और 50 प्रतिशत दालों की खरीद करनी चाहिए। नतीजतन, सिंचित क्षेत्रों के कई किसान गेहूं से सरसों में में बदलाव कर सकते हैं। रोहतक के एक अधिवक्ता किसान जो 2016-17 में कम कृषि कीमतों से तंग आ गया था, एक संकेत दिया— 'मेरे दोस्त के पास ऑस्ट्रेलिया में एक खेत है और उसकी सारी उपज न्यूनतम गारंटीकृत कीमतों पर खेत से उठाई जाती है। लेकिन उसे बुवाई के मौसम से पहले हर साल अपनी उत्पादन योजना को मंजूरी सरकार से लेनी होती है।'

इसका मतलब है कि कृषि उत्पादन अकेले किसानों के लिए नहीं बल्कि समग्र रूप से समाज, देश की आवश्यकता के लिए है। यह संभव हो सकता है, यदि बुवाई के मौसम से पहले, 100 प्रतिशत तिलहन और 50 प्रतिशत दालों के लिए एमएसपी पर खरीद का आश्वासन दिया जाये; तथा गेहूं और धान की खरीद को युक्तिसंगत बनाया जाये यानी सभी 86 प्रतिशत छोटे किसानों को पूरी खरीदारी का वादा। इस नीति के परिणामस्वरूप उर्वरकों और पानी का अधिकतम उपयोग होगा ।

आज का राशिफल

मेष व्यावसायिक समस्या सुलझाने में आप सफल होंगे। रक्तचाप या हृदय रोगी स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। टकराव की स्थिति आपके हित में न होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं।

वृषभ पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

मिथुन आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे।

कर्क राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। खानपान में संयम रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। व्यर्थ के तनाव मिलेंगे

सिंह पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक जनों से तनाव मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे।

कन्या पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। धन लाभ होगा। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। वाणी की सौम्यता आवश्यक है। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।

तुला पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। व्यावसायिक क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अनावश्यक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। किसी अभिन्न मित्र से मिलाप होगा। धन हानि की संभावना है।

वृश्चिक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। विरोधियों का पराभव होगा।

धनु आर्थिक योजना सफल होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। जारी प्रयास सार्थक होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। अनावश्यक कष्ट का सामना करना पड़ेगा।

मकर जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। रोजी रोजगार की दिशा में प्रगति होगी। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। मकान, सम्पत्ति व वाहन की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा।

कुम्भ गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। पारिवारिक जनों से तनाव मिलेगा। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें।

मीन व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

रसायन उत्पादक अनुपम के 760 करोड़ रुपये के आईपीओ को सेबी से मिली मंजूरी

नई दिल्ली। देश की शीर्ष रसायन उत्पाद बनाने वाली अनुपम रसायन को उसके 760 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिये पूंजी बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने आईपीओ के लिये दिसंबर में दस्तावेज जमा कराये थे। उसके बाद कंपनी को सेबी की ओर से 26 फरवरी को जरूरी अवलोकन टिप्पणी मिल गई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की वेबसाइट पर ताजा जानकरी में यह बताया गया है। कोई भी कंपनी आईपीओ, एफपीओ अथवा राइट इश्यू की योजना बनाती है तो उसे सेबी की तरफ से जरूरी अवलोकन कराना होता है। अनुपम रसायन के निर्गम को लेकर तैयार दस्तावेज में कहा गया है कि आईपीओ से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल मुख्य तौर पर कर्ज भुगतान में किया जायेगा। सूरत स्थित इस कंपनी ने अपने आईपीओ का एक हिस्सा अपने कर्मचारियों के लिये आरक्षित रखने का फैसला किया है। वह कर्मचारियों के लिये निर्गम मूल्य में कुछ छूट पर भी विचार कर सकती है।

मासिक डिजिटल भुगतान लेनदेन में पेटीएम ने 1.2 अरब का आंकड़ा पार किया

नई दिल्ली। आनलाइन भुगतान प्रणाली में पेटीएम ने रिकार्ड कायम किया है कंपनी ने कहा कि उसका मासिक डिजिटल भुगतान लेनदेन 1.2 अरब को पार कर गया है। कंपनी ने दावा किया ऑफलाइन भुगतान और वित्तीय सेवाओं में ऊंची वृद्धि के कारण वह यह आंकड़ा हासिल कर पाई है। कंपनी ने कहा कि ऑफलाइन मर्चेंट भुगतान बाजार में उसकी बाजार हिस्सेदारी सबसे अधिक है। माह-दर-माह आधार पर इसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। पेटीएम के उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव ने बयान में कहा, बड़ी संख्या में हमारे प्रयोगकर्ताओं ने पेटीएम के साथ डिजिटल यात्रा शुरू की थी। अब उन्होंने हमारी वित्तीय सेवाओं को अपना लिया है।

फरवरी माह में भारतीय ग्राहकों को अच्छी लगी टोयोटा की कारें, ब्रिकी 36 फीसदी बढ़ी

मुंबई। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने फरवरी महीने की सेल्स रिपोर्ट जारी कर दी है। कंपनी ने बताया है कि फरवरी 2021 में उसके कुल 14,075 यूनिट्स की बिक्री हुई। जबकि, फरवरी 2020 में टोयाटा के कुल 10,352 यूनिट्स की घरेलू बाजार में बिक्री हुई थी। इसकी तुलना अगर पिछले साल के फरवरी महीने से करें,तब फरवरी महीने टोयोटा की बिक्री में 36 फीसदी की बढ़ोतरी आई है। हालांकि, इसकी तुलना अगर जनवरी 2021 से करें,तब इस दौरान कंपनी की बिक्री में 27 फीसदी की महीना दर महीना बढ़त दर्ज की गई है। बता दें कि जनवरी 2021 में टोयोटा की कुल 11,126 गाड़ियों की भारतीय बाजार में बिक्री हुई थी। टोयोटा इंडिया ने जनवरी 2021 में 11,126 यूनिट्स की भारतीय बाजार में बिक्री थी। जबकि, जनवरी 2020 में टोयाटा के कुल 5,804 यूनिट्स की घरेलू बाजार में बिक्री हुई थी। जनवरी महीने में कंपनी की बिक्री में 92 फीसदी की साल दर साल बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।

फर्टिलाइजर, फुटवियर, फर्नीचर और टेक्सटाइल्स कंपनियों को राहत दे सकती हैं मोदी सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)।

नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना संकट के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे सेक टर्स को उबारने की हरसंभव कोशिश कर रही है। इस कड़ी में अब फर्टिलाइजर, फुटवियर, फर्नीचर और टेक्सटाइल्स कंपनियों के लिए अच्छी खबर है।

दरअसल, केंद्र सरकार फर्टिलाइजर कंपनियों को मार्च 2021 के आखिर तक खाद सब्सिडी का पूरा बकाया भुगतान कर सकती है। बता दें कि फर्टिलाइजर कंपनियों को अब तक सब्सिडी का 86 फीसदी भुगतान किया जा चुका है।

फर्टिलाइजर कंपनियों को खाद सब्सिडी के भुगतान में काफी तेजी आई है। फरवरी 2021 में कंपनियों को 19,000 करोड़ रुपये सब्सिडी का भुगतान किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अब मार्च 2021 में करीब 21,000 करोड़ रुपये का सब्सिडी भुगतान करने की तैयारी है। कारोबारी साल में अब तक कुल आवंटन का 86 फीसदी सब्सिडी भुगतान हो चुका है। सब्सिडी के 136 करोड़ रुपये में से करीब 117 करोड़ रुपये बकाया दिया जा चुका है। सबसे ज्यादा 75 फीसदी सब्सिडी यूरिया बनाने वाली कंपनियों को मिली है। ज्यादा सब्सिडी पाने वाली कंपनियों में आरसीएफ, चंबल फर्टिलाइजर, जुआरी ग लोबल, कोरोमंडल, यूपीएल और इफको शामिल हैं।

केंद्र सरकार फुटवेयर, फर्नीचर और टेक्सटाइल्स सेक्टर को भी राहत दे सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन तीनों उद्योगों से जुड़ी कंपनियों को वस्तु व सेवा कर में राहत की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार का इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर दुरुस्त करने पर जोर है।

कच्चे माल पर भारी जीएसटी से कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं। फुटवेयर के कच्चे माल पर 12 फीसदी से 18 फीसदी जीएसटी लगाता है। फिलहाल 1000 से कम के फुटवियर पर 5 फीसदी जीएसटी है, मोदी सरकार इसमें राहत दे सकती है।

आज से देशभर के शोरूम से शुरु होगी रेनाल्ट कीगर की डिलेवरी

नई दिल्ली (एजेंसी)।

रेनाल्ट अपनी पहली सबकॉम्पैक्ट एसयूवी रेनाल्ट कीगर की बुधवार से डिलीवरी शुरू करने जा रही है। दरअसल कंपनी ने एसयूवी को पिछले महीने भारतीय बाजार में ही लांच कर दिया था, लेकिन तब इसकी डिलीवरी शुरू नहीं की गई थी। बता दें कि रेनाल्ट कीगर कंपनी के सीएमएफ-ए प्लेटफॉर्म पर काम करती है और भारतीय बाजार में शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.45 लाख रुपये है। रेनाल्ट कीगर दो इंजन ऑप्शन के साथ बाजार में उपलब्ध है। इनमें 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.0-लीटर टर्बो-चार्ज्ड पेट्रोल इंजन शामिल हैं। 3-सिलिंडर,1-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन- इसका 999 सीसी का इंजन 5000 आरपीएम 100 पीएस और 2800-3600 आरपीएम पर 160 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इसका इंजन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है। इसका 999 सीसी का इंजन 6250 आरपीएम 72 पीएस और 3500 आरपीएम पर 96 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इसका इंजन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है। इसके अलावा इसमें 5-स्पीड इजी-आएएमटी का भी विकल्प मिलता है। इसका 999 सीसी का इंजन 5000 आरपीएम 100 पीएस और 2400-4400 आरपीएम पर 152 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इसका इंजन एक्स-ट्राइन-सीवीटी से लैस है। यह सबकॉम्पैक्ट एसयूवी 6 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। इनमें कैसपियन ब्लू, रेडियंट रेड, मूनलाइट सिल्वर, प्लेनेट ग्रे, आइस कूल व्हाइट और महोगेनी शामिल हैं। इसकी लंबाई 3,991 मिलीमीटर, चौड़ाई 1,750 मिलीमीटर और ऊंचाई 1,600 मिलीमीटर है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2500 मिलीमीटर है। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 205 मिलीमीटर है।

'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों में चुनौतियों का प्रतीक बना : रिपोर्ट

वॉशिंगटन (एजेंसी)।

राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी संसद से कहा है कि भारत में हाल में शुरू किया गया 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में खड़ी होने वाली चुनौतियों का प्रतीक बन गया है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने अपनी 2021 की व्यापार नीति एजेंडा और 2020 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि 2020 के दौरान अमेरिका ने लगातार भारत के साथ बाजार पहुंच से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिये प्रयास जारी रखा। यूएसटीआर की सोमवार को कांग्रेस को सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है, 'भारत का बड़ा बाजार, आर्थिक वृद्धि और विकास की ओर अग्रसर उसकी अर्थव्यवस्था जहां उसे अमेरिकी निर्यातकों के लिये आवश्यक बाजार बनाती है वहीं दूसरी तरफ भारत में सामान्य तौर पर व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाली नीतियों के चलते द्विपक्षीय व्यापार संभावनाओं को कम किया है। भारत में हाल में आयात के विकल्प के तौर पर शुरू किये गये 'मेक इन इंडिया' अभियान ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के समक्ष चुनौतियों को बढ़ा दिया है। अमेरिका ने 5 जून 2019 से सामन्यीकृत तरजीही प्रणाली (जीएसपी) कार्यक्रम के तहत भारत की पात्रता को समाप्त कर दिया था। अमेरिका ने यह कदम जीएसपी बाजार पहुंच मानदंड के मामले में भारत के अनुपालन पात्रता को लेकर उठी चिंताओं की समीक्षा के बाद उठाया। जीएसपी के तहत भारत को मिलने वाले व्यापार लाभ निलंबित कर दिये जाने के बाद से ही अमेरिका और भारत 2019 से तार्किक बाजार पहुंच पैकेज पर काम करने में जुटे हुये हैं। वर्ष 2020 में भी यह काम जारी रहा। इस बातचीत में अमेरिका का उद्देश्य भारत में कई तरह की गैर-शुल्कीय बाधाओं को दूर करना, विभिन्न शुल्कों में लक्षित कमी लाना और भारत में अमेरिकी उत्पादों के लिये बाजार पहुंच में सुधार लाना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में अमेरिका में आयात की गई सेवाओं में 62।3 अरब डालर के साथ ब्रिटेन लगातार सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा। वहीं भारत 29।7 अरब डालर की सेवाओं के आयात के साथ छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा। कनाडा से 38।6 अरब डालर, जापान से 35।8 अरब डालर, जर्मनी से 34।9 अरब डालर और मैक्सिको से 29।8 अरब डालर की सेवाओं का आयात किया गया।

18 पैसों की मजबूती के साथ रुपया 73.37 पर बंद

मुंबई। करोबारी सप्ताह के दूसरे दिन रुपए में मजबूती देखने को मिली। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मंगलवार को 18 पैसे की मजबूती के साथ 73.37 पर बंद हुआ। मुद्रा बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 73.32 पर खुला तथा कारोबार के अंत में पिछले दिन के मुकाबले 18 पैसे की मजबूती के साथ 73.37 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। वहीं पिछले दिन यानी सोमवार को रुपया 8 पैसों की गिरावट के साथ 73.55 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

सेंसेक्स 447 अंक मजबूत होकर फिर से 50,000 के ऊपर निकला

मुंबई (एजेंसी).

घरेलू और वैश्विक स्तर पर सकारात्मक रुख के बीच वाहन, बैंक और आईटी कंपनियों के शेयरों में तेज लिवाली से बीएसई सेंसेक्स मंगलवार को 447 अंक की मजबूती के साथ 50,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 447.05 अंक यानी 0.90 प्रतिशत की बढ़त के साथ 50,296.89 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 157.55 अंक यानी 1.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 14,919.10 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक लाभ में महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, टीसीएस और मारुति रही। दूसरी तरफ, ओएनजीसी, एचडीएफसी, डा. रेड्डीज, पावर ग्रिड और एसबीआई को नुकसान हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 लाभ के साथ बंद हुए। विश्लेषकों के अनुसार तीसरी तिमाही में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में वृद्धि से

निवेशक उत्साहित हैं।

साथ ही वैश्विक बांड बाजारों में पिछले सप्ताह के उठा-पटक के बाद स्थिरता से भी धारणा मजबूत हुई है। एशिया के अन्य बाजारों... तोक्यो, शंघाई और हांगकांग में गिरावट (रिपीट गिरावट) रही। इस बीच, ब्रेंट क्रूड वायदा 0.71 प्रतिशत मजबूत होकर 63.76 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिका डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे मजबूत होकर 73.37 पर बंद हुआ।

कोटक महिंद्रा बैंक ने आवास ऋण में ब्याज घटाकर 6.65 फीसदी किया

मुंबई।

निजी क्षेत्र के अग्रणी कोटक महिंद्रा बैंक ने आवास ऋण ब्याज में 0.10 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की। सीमित अवधि की इस कटौती के बाद ब्याज दर 6.65 प्रतिशत पर आ गई है। इस कटौती के साथ बैंक का दावा है कि वह ग्राहकों को बाजार में सबसे कम ब्याज पर आवास ऋण उपलब्ध कराएगा। बैंक ने एक बयान में कहा कि विशेष पेशकश के तहत ग्राहक 31 मार्च तक 6.65 प्रतिशत पर कर्ज ले सकेंगे। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (भारतीय स्टेट बैंक) के ब्याज दर घटाकर 6.70 प्रतिशत किये जाने के कुछ ही घंटे बाद कोटक बैंक ने यह घोषणा की है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा कि ब्याज दर कर्जदार के 'क्रेडिट स्कोर' और मूल्य के अनुपात में कर्ज (एलटीवी) पर निर्भर करेगी।

घट सकती हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें, उत्पाद शुल्क में कटौती करने पर विचार कर रही सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)।

पेट्रोल-डीजल की आसमान छू रही कीमतों से हर कोई परेशान है। कई राज्यों में तो पेट्रोल 100 रुपए से भी अधिक कीमत का हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक, अब केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के सूत्र ने बताया कि, सरकार कीमतों को जल्द कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने पर विचार कर रही है। उल्लेखनीय है कि पेट्रोल-डीजल के महंगे होने के सबसे बड़ा कारण टैक्स ही है। केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क और राज्य वैट वसूलते हैं। अभी केंद्र और राज्य सरकारें उत्पाद शुल्क एवं वैट के नाम पर 100 फीसदी से ज्यादा टैक्स वसूल रही हैं। इन दोनों की दरें इतनी ज्यादा है कि 35 रुपए का पेट्रोल विभिन्न राज्यों में 90 से 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों पर मचे हाहाकार के बीच सूत्रों ने कहा है कि वित्त मंत्रालय ने कुछ राज्यों, तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ परामर्श शुरू किया है, ताकि उपभोक्ताओं पर टैक्स का बोझ कम करने का सबसे प्रभावी तरीका निकाला जा सके। इसके अलावा यदि केंद्र पेट्रोलियम उत्पादों को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के दायरे में ले आए तो आम आदमी को राहत मिल सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसके संकेत दिए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 91.17 रुपए और मुंबई में 97.57 रुपए प्रति लीटर है। वहीं, दिल्ली में डीजल 81.47

रुपए और मुंबई में 88.60 रुपए प्रति लीटर है। पिछले महीने राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गए थे। ये दोनों राज्य तेलों पर सबसे अधिक वैट लेते हैं।

आईपीओ से पहले फ्लिपकार्ट ने नेतृत्व में किया परिवर्तन, हेमंत बद्री का हुआ प्रवेश

बेंगलुरु (एजेंसी)।

अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट के मालिकाना हक वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने लीडरशिप में बदलाव किया है। कंपनी ने यूनिलीवर के पूर्व ग्लोबल एग्जीक्यूटिव हेमंत बद्री को सप्लाई चेन ऑपरेशंस के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट दो अन्य सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की भूमिकाओं में बदलाव और विस्तार कर रही है। बद्री यूनिलीवर में वर्ल्डवाइड प्लानिंग, कस्टमर सर्विस व यूरोप ऑपरेशनल प्लानिंग के वाइस प्रेसिडेंट थे। उनकी नियुक्ति की घोषणा फ्लिपकार्ट के गुप सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति ने कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल के जरिए की। फ्लिपकार्ट में लीडरशिप में हुए बदलाव 1 मार्च 2021 से प्रभावी होंगे। कृष्णमूर्ति ने फ्लिपकार्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमितेश झा की भूमिका में बदलाव का भी ऐलान किया है। अमितेश पहले फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जीव्स और कंपनी के कुछ अन्य बिजनेस की सप्लाई चेन को हेड करते थे। ईमेल में कृष्णमूर्ति ने लिखा है कि अब अमितेश कैटेगरी डिजाइन ऑपरेशंस (सीडीओ) और एम3 (मार्केटिंग, मर्चेंडाइज व मोनेटाइजेशन) ऑर्गेनाइजेशन में नई भूमिका निभाएंगे, जिसमें वह कंज्यूमेबल्स, सॉफ्टलाइन्स और कस्टमर व मार्केटिंग चार्टर्स की देखरेख करेंगे। वहीं फिनटेक व पेमेंट्स ग्रुप को हेड करने वाले रंजीत बोयानापल्ली अब कस्टमर एक्सपीरियंस, मार्केटप्लेस और सेंट्रल लिक्विडेशन टीम (सीएलटी) का अतिरिक्त चार्टर भी संभालेंगे। कृष्णमूर्ति के ईमेल में रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के उन बदलावों का भी जिक्र है, जो टॉप मैनेजमेंट में बदलावों के चलते होंगे। कहा गया है कि अमितेश झा अगले कुछ महीनों तक बद्री को डायरेक्टली मैनेज और मेंटोर करेंगे। फ्लिपकार्ट के टॉप मैनेजमेंट में यह बदलाव उस वक्त हुआ है, जब कंपनी अपने आईपीओ इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग को लाने की तैयारी कर रही है। फ्लिपकार्ट का आईपीओ इस साल के आखिर तक आने का अनुमान है और इसकी वैल्युएशन 40 अरब डॉलर रह सकती है। इससे पहले फ्लिपकार्ट ने अपने निदेशक मंडल में दिसंबर 2020 में बदलाव किया था। कंपनी ने बोर्ड में सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति समेत 4 नए चेहरों को शामिल किया था। फ्लिपकार्ट बोर्ड के बाकी नए सदस्यों में एचडीएफसी सीईओ केकी मिस्त्री, वॉलमार्ट के ग्लोबल चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर सुरेश कुमार और वॉलमार्ट में इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी व डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट लिख हॉपक्सि शामिल हैं।

मोबाइल कैटरिंग अनुबंध रद्द करने के बाद आईआरसीटीसी के शेयरों में गिरावट

नई दिल्ली (एजेंसी)।

आईआरसीटीसी के शेयरों में मंगलवार को गिरावट देखी गई। सुबह 9.36 बजे आईआरसीटीसी के शेयर 1.55 फीसदी गिरकर 1909.05 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। इससे पहले सोमवार शाम रेल मिनिस्ट्री ने आईआरसीटीसी को सभी तरह के मोबाइल केटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने को कहा है। मंत्रालय ने रेगुलेटर को दी गई जानकारी में बताया कि आईआरसीटीसी को सभी मोबाइल कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द करना होगा, फिर चाहे वह ट्रेन से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को बेस किचन में तैयार किया गया खाना ही क्यों न परोस रहे हों। ट्रेनों में मोबाइल कैटरिंग की सुविधा 2014 में शुरू की गई थी, जिसमें यात्री अपने फेवरेट ब्रांड से ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते थे और पैसेंजर्स को उनकी ऑर्डर किया हुआ फूड उनके बर्थ पर डिलिवर होता था। रेल मंत्रालय ने कहा कि इसे कोरोना वायरस के कारण उपजे हालात की वजह से एक्सेप्शन मानें और इसे कॉन्ट्रैक्टर की गलती के रूप में नहीं देखा जाए। रेल मंत्रालय ने केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने का आदेश देते हुए कहा है कि अब खाना नहीं परोसने पर किसी भी फूड कॉन्ट्रैक्टर पर फाइन नहीं लगाया जाएगा। उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट और एडवांस लाइसेंस फीस बकाया पेमेंट में एडजस्ट करके लौटा दिया जाएगा। दरअसल, 19 जनवरी 2021 को मद्रास हाईकोर्ट में इंडियन रेलवे मोबाइल केटरर्स एसोसिएशन (आईसीआरएमसीए) ने यह मुद्दा उठाते हुए मांग की थी कि उन्हें रेलवे की केटरिंग में अपनी सर्विस रिस्टोर करने की इजाजत दी जाए, जो लॉकडाउन के कारण मार्च, 2020 से ही बंद है। रेल मंत्रालय का यह आदेश कोर्ट में इस पीटिशन के बाद आया है। इससे पहले रेलवे ने कहा था कि फरवरी से ट्रेनों में ई-कैटरिंग की सुविधा शुरू कर दी जाएगी।

टैबलेट सेगमेंट में 14.7 फीसदी बढ़ोतरी, ई-लर्निंग की वजह से बढ़ी मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारत में कोरोना संकट की वजह से लोगों की निर्भरता आनलाइन क्लासेज यानी ई-लर्निंग पर बढ़ गई है। पिछले साल यानी 2020 में लोगों ने ऑफिस के काम के साथ बच्चों की पढ़ाई के वास्ते कंप्यूटर, टैबलेट के साथ ही स्मार्टफोन्स भी खूब खरीदारी की। आलम यह रहा कि भारत में बिक्री के मामले में टैबलेट सेगमेट में 14.7 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली। यह ग्रोथ काफी ज्यादा है। पिछले साल सैमसंग ने टैबलेट सेगमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ दर्ज कराई, वहीं ऐपल के iPad की भी बंपर बिक्री हुई। सैमसंग के टैबलेट की बिक्री में बीते साल 157 फीसदी की सालाना उछाल देखने को मिली। आईडीसी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2020 में इंडिया के टैबलेट मार्केट मं 14.7 फीसदी की उछाल देखने को मिली। दरअसल, पिछले साल कई कंपनियों ने भारत में अफॉर्डेबल यानी किफायती टैबलेट लॉन्च किए, जो लोगों की जेब पर बोझ नहीं बने और लोगों ने अपने बच्चों की पढ़ाई के वास्ते इसकी खरीदारी की, इस वजह से साल 2020 में कई कंपनियों के सस्ते-महंगे टैबलेट की बंपर खरीदारी हुई।

आईडीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऑनलाइन क्लास यानी ई-लर्निंग पर जोर देने की वजह से लोगों ने अपने बच्चों के लिए टैबलेट खरीदे, क्योंकि स्मार्टफोन पर लंबे समय तक क्लास करना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। आईडीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में बजट सेगमेंट के टैबलेट यानी 10 से 20 हजार रुपए के बीच के रेंज के टैबलेट की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है और सन 2020 में इस सेगमेंट के टैबलेट की बिक्री में 70 फीसदी से ज्यादा की सालाना ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि, इन सबके बीच सैमसंग और ऐपल के प्रीमियम टैबलेट की भी अच्छी खासी बिक्री हुई। लोगों ने सैमसंग गैलेक्सी टैब एस6 लाइट और एप्पल के 10.2 इंच के आईपैड की खूब खरीदारी की।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

Sports

तोक्यो ओलंपिक कार्यकारी बोर्ड में 12 और महिलाओं को मिली जगह

तोक्यो : तोक्यो ओलंपिक ने लैंगिक समानता की ओर प्रतीकात्मक कदम उठाते हुए बोर्ड में 12 और महिलाओं को शामिल किया जिससे 45 सदस्यीय समिति में उनकी संख्या 19 (लगभग 42%) हो गयी। इस समिति में महिलाओं को शामिल करने के लिए बोर्ड में सदस्यों की संख्या को 35 से बढ़ाकर 45 हो गयी जबकि कुछ सदस्यों को इस्तीफा भी देना पड़ा। कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद इस कदम की घोषणा मुख्य कार्यकारी अधिकारी तोशीरो मुतो ने की। नए सदस्यों के नामों की घोषणा बुधवार को होने की उम्मीद है। आयोजन समिति की नयी अध्यक्ष सीको हाशिमोतो की पहल पर यह बदलाव किए गए। पिछले महीने 83 साल के पूर्व अध्यक्ष योशिरो मोरी के इस्तीफे के बाद हाशिमोतो अध्यक्ष नियुक्त हुई है। मोरी ने महिलाओं के खिलाफ लैंगिंग टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि महिलाएं काफी बातें करती हैं। हाशिमोतो ने बोर्ड की बैठक की शुरुआत में कहा कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के मामले में हमारा मानना है कि आयोजन समिति में विश्वास बहाल करने के लिए तेजी से काम कर ठोस परिणाम देना होगा।

एक बार फिर साथ दिखेगी बोपन्ना-कुरैशी की जोड़ी, अकापुल्को एटीपी में खेलेंगे साथ

नई दिल्ली (एजेंसी)।

'भारत-पाक एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर रोहन बोपन्ना और ऐसाम-उल-हक कुरैशी की जोड़ी छह साल के बाद एक बार फिर से 15 मार्च से मेक्सिको में खेले जाने वाले अकापुल्को एटीपी 500 में टेनिस कोर्ट पर एक साथ दिखेगी। इससे पहले यह जोड़ी 2014 शेनजेन एटीपी 250 प्रतियोगिता में एक साथ खेली थी। भारत-पाक के खराब राजनायिक संबंध के कारण सुर्खियां बटोरने वाली इस जोड़ी की सबसे बड़ी सफलता 2010 में यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचना था, जहां उन्हें ब्रायन बंधुओं की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा था।बोपन्ना उस समय अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग तीसरे स्थान तक पहुंचे थे बोपन्ना ने इसके बाद 2012 ओलंपिक की तैयारियों के लिए दिग्गज महेश भूपति के साथ जोड़ी बनाकर खेलने का फैसला किया। भारत और पाकिस्तान के 40 बरस के इन खिलाड़ियों की जोड़ी फिलहास सिर्फ एक टूर्नामेंट में साथ खेलेगी। कुरैशी ने कहा कि अभी हम सिर्फ मैक्सिको में खेलने के लिए एक साथ आ रहे हैं। अभी तक हमने भविष्य के बारे में बात नहीं की है। यह पूछे जाने पर कि क्या यह एक लंबी अवधि की व्यवस्था हो सकती है, कुरैशी ने कहा कि उम्मीद है, अगर यह अच्छी तरह से चलता है तो हम भविष्य में साथ में और अधिक टूर्नामेंट खेल सकते हैं। वे वास्तव में दुबई ड्यूटी फ्री चैंपियनशिप में एक साथ प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी योजना सफल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में एक साथ बहुत समय बिताया। हम दुबई में खेलने की योजना बना रहे थे। उसे एक जोड़ीदार की जरूरत थी और मुझे भी एक जोड़ीदार की जरूरत थी। इसलिए हमने सोचा कि चलो दुबई ओपन के लिए टीम बनाई जाए, दुर्भाग्य से हम इसके लिए क्वालीफाई नहीं कर सकें। हमारी संयुक्त रैंकिंग उस स्तर की नहीं थी। उन्होंने कहा कि लेकिन हम अकापुल्को में जगह बनाने में सफल रहे। मैं बहुत उत्साहित हूँ। उम्मीद है, हम एक साथ अच्छा खेलेंगे और यह सफल रहेगा। तब हम कुछ और टूर्नामेंट एक साथ खेलने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इसी टूर्नामेंट के लिए साथ आये है। मुझे नहीं पता कि 2021 के लिए उनकी (बोपन्ना) योजना क्या है। उन्होंने किसी के साथ जोड़ी बनाने का फैसला किया है या नहीं।

हम देखेंगे स्थिति कैसी रहती है। बोपन्ना और कुरैशी ने शांति संदेश फैलाने के लिए 'स्टॉप वॉर, स्टार्ट टेनिस' अभियान शुरू किया था। जिसे 'अर्थर एश मानवता' पुरस्कार भी मिला था।

ला लीगा : रियल मेड्रिड ने रियल सोसिएदाद के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला

ला लीगा (एजेंसी)।

रियल मेड्रिड ने रियल सोसिएदाद के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला 1मेड्रिड, 2 मार्च । रियल मेड्रिड और रियल सोसिएदाद के बीच ला लीगा का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, इस ड्रॉ के बाद अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद रियाल मेड्रिड और शीर्ष पर मौजूद एटलेटिको मेड्रिड के बीच पांच अंकों का फासला हो गया है। रियल मेड्रिड और रियल सोसिएदाद के बीच पहले हॉफ तक मुकाबला गोल रहित रहा था। लेकिन रियल सोसिएदाद की ओर से पोंतू ने 55वें मिनट में गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। रियल मेड्रिड जहां एक तरफ बराबरी करने की कोशिश कर रही थी वहीं, रियल सोसिएदाद बढ़त हासिल करना चाह रही थी। रियल मेड्रिड को अंतिम मिनट में सफलता मिली और उसकी ओर से 89वें मिनट में विनिकिअस जूनियर ने गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया।निर्धारित समय तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकीं और मुकाबला 1-1 से ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इस मैच के बाद रियल मेड्रिड 25 मैचों में 53 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

मियामी ओपन में नहीं खेलेंगे पूर्व नंबर एक खिलाड़ी रोजर फेडरर

मियामी । दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी रोजर फेडरर ने इस महीने होने वाले मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है जिससे कि टूर में वापसी की अपनी तैयारी को अधिक समय दे सकें। फेडरर के एजेंट ने यह जानकारी दी। पिछले सत्र में दाएं घुटने के 2 आपरेशन के बाद 20 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन फेडरर एक साल से अधिक समय से प्रतिस्पर्धी टेनिस नहीं खेले हैं। अगस्त में 40 बरस के होने वाले फेडरर की अगले महीने कतर के दोहा में 14 मार्च से शुरू हो रहे हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट के साथ टूर पर वापसी की योजना है। फेडरर को 24 मार्च से मियामी में शुरू हो रहे मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेना था लेकिन उनके एजेंट टोनी गॉडसिक ने सोमवार को बताया कि वह वहां नहीं खेलेंगे। गॉडसिक ने ईमेल पर एपी को बताया, 'दोहा और शायद दुबई के बाद, (फेडरर) वापस जाएगा और ट्रेनिंग करेगा।

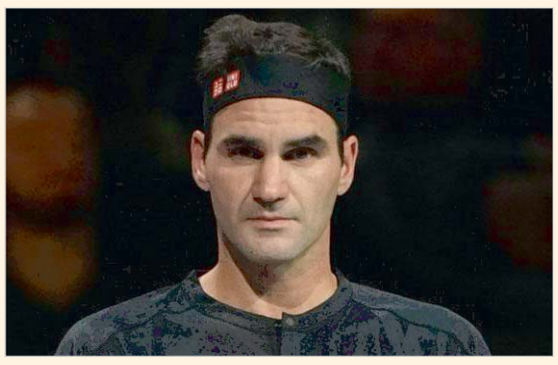

सानिया की दोहा में जीत के साथ डब्ल्यूटीए सर्किट पर वापसी

दोहा (एजेंसी)।

सानिया मिर्जा ने डब्ल्यूटीए सर्किट में जीत के साथ वापसी की जब उन्होंने और स्लोवाकिया की उनकी जोड़ीदार आंद्रेजा क्लेपैक ने नादिया किचेनोक और ल्युडमाइला किचेनोक की युक्रेन की जोड़ी को हराकर यहां कतर टोटल ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत और स्लोवेनिया की जोड़ी ने सोमवार रात डब्ल्यूटीए 500 टूर्नामेंट के पहले दौर में नादिया और ल्युडमाइला की जोड़ी को 6-4, 6-7, 10-5, से हराया। सानिया का 12 महीने में यह पहला प्रतिस्पर्धी मुकाबला था। वह पिछली बार फरवरी 2020 में दोहा ओपन में ही खेली थी जिसके बाद कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में टेनिस प्रतियोगिताएं ठप पड़ गईं थी। सानिया स्वयं भी इस साल जनवरी में कोरोना वायरस संक्रमण से उबरी हैं। सानिया मातृत्व अवकाश के बाद जब प्रतिस्पर्धी टेनिस में लौटी थी तो उन्होंने नादिया के साथ ही जोड़ी बनाई थी और पिछले साल जनवरी में होबार्ट ओपन का खिताब जीता था। सानिया और आंद्रेजा ने हालांकि पहले सेट के शुरू में ही अपनी सर्विस गंवाई जिससे यह जोड़ी 0-3 से पिछड़ गई। चौथे गेम में भी यह जोड़ी अपनी सर्विस गंवाने के कगार पर थी लेकिन स्कोर 1-3 करने में सफल रही। भारत और स्लोवेनिया की जोड़ी ने सातवें गेम में किचेनोक बहनों की सर्विस तोड़कर वापसी की और स्कोर 4-4 किया। नौवें गेम में युक्रेन की जोड़ी की सर्विस तोड़ने और फिर अपनी सर्विस बचाकर सानिया और आंद्रेजा ने पहला सेट जीता। युक्रेन की जोड़ी ने दूसरे सेट में सानिया और आंद्रेजा की सर्विस तोड़कर 3-1 की बढ़त बनाई। भारत और स्लोवेनिया की जोड़ी ने सेट को टाईब्रेकर तक खींचा लेकिन हार गईं। सुपर टाईब्रेकर में सानिया और आंद्रेजा छाई रही। इस जोड़ी को 5-1 की बढ़त बनाने के बाद मुकाबला जीतने में अधिक परेशानी नहीं हुई।

संक्षिप्त समाचार

ICC Rankings : स्मृति मंधाना को लगा झटका, झूलन 5वें स्थान पर बरकरार

दुबई । भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना मंगलवार को जारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की महिला एकदिवसीय खिलाड़ी रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में 2 स्थान के नुकसान से 6 स्थान पर खिसक गई जबकि झूलन गोस्वामी गेंदबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर बरकरार है। एक अन्य अनुभवी खिलाड़ी मिताली राज 687 अंक के साथ 9वें स्थान पर हैं और बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल दूसरी भारतीय बल्लेबाज हैं। स्मृति के 732 अंक हैं। इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज टैमी ब्युमोंट न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में 2-1 की जीत के दौरान शानदार प्रदर्शन की बदौलत पांच स्थान की छलांग के साथ शीर्ष पर पहुंच गई हैं। टैमी ने वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर और न्यूजीलैंड की ऐमी सेटरथवाइट जैसी खिलाड़ियों को पछाड़ा और दूसरे स्थान पर मौजूद आस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लेनिंग पर 16 अंक की बढ़त बना ली है। झूलन (691), पूनम यादव (679), शिखा पांडे (675) और दीप्ति शर्मा (639) गेंदबाजों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल हैं। ये सभी अपनी पिछली रैंकिंग पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया की जेस जोनासेन 804 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर कायम हैं। उनके बाद उनकी हमवतन मेगान शुट (735) का नंबर आता है। आलराउंडरों की सूची में दीप्ति 359 अंक के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिस पैरी शीर्ष पर चल रही हैं।

डेल स्टेन का बड़ा बयान, आईपीएल से ज्यादा पीएसएल में मिलता है सम्मान

(एजेंसी)।

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन पाकिस्तान की टी20 लीग पीएसएल में खेल रहें हैं। पीएसएल में डेल स्टेन ने आईपीएल को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्टेन ने आईपीएल पर बात करते हुए कहा कि आईपीएल में क्रिकेट को नहीं बल्कि पैसों को लेकर बात होती है। यही कारण है कि आईपीएल के नए सीजन के लिए उन्होंने अपना नाम वापिस ले लिया और इसकी जानकारी अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को दी। स्टेन ने पाकिस्तान क्रिकेट से बात करते हुए कहा कि मैंने दूसरी क्रिकेट लीग खेलकर यह पाया कि बतौर खिलाड़ी आईपीएल से अधिक मुझे इनमें सम्मान मिल रहा है। मुझे लगता है कि जब आप आईपीएल में जाते हैं, तो इतने बड़े स्क्वाड और इतने बड़े नाम होते हैं और शायद इस बात पर ज्यादा अधिक जोर दिया जाता है कि खिलाड़ी की कितने पैसे कमा रहा है यही कारण है कि कई बार आईपीएल में क्रिकेट को भूला दिया जाता है। स्टेन ने आगे कहा कि जब आप एक पीएसएल या श्रीलंकाई प्रीमियर लीग आते हैं तो वहां क्रिकेट को अधिक महत्व दिया जाता है। मैं केवल कुछ दिनों के लिए यहां आया हूं और मेरे कमरे के अंदर और बाहर के लोग हैं, बस यह जानना चाहते हैं कि मैंने कहां खेला है और मैं वहां कैसे गया। वहीं जब मैं आईपीएल जैसी लीग में खेलने के लिए जाता हूं तो सब भूल जाते हैं और सिर्फ एक ही विषय रह जाता है कि तुम आईपीएल में कितने पैसे कमाए। उन्होंने आगे कहा कि सच कहूं तो मैं आईपीएल से दूर रहना चाहता हूं। मैं अच्छी क्रिकेट और अच्छा टूर्नामेंटों के लिए अच्छे वाइब्स लाने के लिए दूसरी लीग में खेल रहा हूं जिसके मैं लायक भी हूं। गौर हो कि स्टेन आईपीएल में 95 मैच खेलें हैं जिसमें उन्होंने 97 विकेट अपने नाम किए हैं। वह आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, डैक्कन चार्जर्स, सनराईजर्स हैदराबाद और गुजरात लायंस के लिए मैच खेला है।

प्लेयर ऑफ द मंथ : अश्विन, रूट और मायर्स के बीच मुकाबला

दुबई । अनुभवी भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और वेस्टइंडीज के नए बल्लेबाजी सनसनी कायल मायर्स फरवरी में शानदार प्रदर्शन के दम पर मंगलवार को आईसीसी 'प्लेयर ऑफ द मंथ (महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी) पुरस्कार के लिए नामित किए गए। अश्विन ने इस दौरान इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैच खेले जिसमें चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट में गेंद से कमाल करने के साथ उन्होंने दूसरी पारी में 106 रन बनाए थे। उन्होंने अहमदाबाद में तीसरे टेस्ट में अपने विकेट की संख्या को 400 के पार पहुंचा दिया। आईसीसी से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, 'कुल 176 रन बनाने के साथ 24 विकेट लेकर अश्विन पुरूष वर्ग में फरवरी महीने के नामांकन के हकदार हैं। उन्होंने कहा, 'इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट ने बल्ले और गेंद के साथ शानदार प्रदर्शन के लिए इस महीने फिर से नामांकन की सूची में जगह बनाई है। उन्होंने भारत के खिलाफ खेले गए 3 टेस्ट मैचों में कुल 333 रन बनाए और 6 विकेट झटके है। पिछले महीने भी नामांकन में जगह पाने वाले रूट ने भारत के खिलाफ मौजूदा श्रृंखला के पहले मैच में 218 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज के लिए पदार्पण करते हुए मायर्स ने दूसरी पारी में 210 रन बनाए जिससे उनकी टीम 395 रन के लक्ष्य को हासिल करने में सफल रही। महिला वर्ग में, न्यूजीलैंड की ब्रुक हॉलिडे के साथ इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट और नैट स्किवर को नामांकित किया गया है।

PSL में तीन और खिलाड़ियों को हुआ कोरोना, PCB ने दिया बड़ा बयान

कराची । पाकिस्तान सुपर लीग में दो विदेशी खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ का एक सदस्य कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया है लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को कहा कि टूर्नामेंट पर इसका कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया निदेशक सामी बर्नी ने संक्रमित पाए गए तीन व्यक्तियों के नाम नहीं बताए। इससे पहले आस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर फवाद अहमद पॉजिटिव पाए गए थे जो क्वारंटीन हैं। बर्नी ने नेशनल स्टेडियम पर प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मैं इसकी पुष्टि करता हूं कि दो विदेशी खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ का एक सदस्य कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया है। उन्होंने बताया कि एक क्रिकेटर इस्लामाबाद युनाइटेड टीम का है जिसके खिलाड़ी फवाद अहमद को पहले ही पॉजिटिव पाया गया है। पीसीबी अधिकारी ने यह भी कहा कि एक और टीम के जांच नतीजे अभी आने बाकी है। उन्होंने कहा कि टीम मालिकों के साथ वर्चुअल बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल और बायो बबल संबंधी दिशा निर्देशों का और कड़ाई से पालन करने के मुताल्लिक बात की गई।

पुलिस ने बार्सीलोना के पूर्व अध्यक्ष को हिरासत में लिया

मैड्रिड : स्पेन की पुलिस ने बार्सीलोना स्टेडियम में छापे की कार्रवाई के बाद इस फुटबॉल कलब के पूर्व अध्यक्ष जोसेप मारिया बोर्टोम्यु सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई उस समय की गई जब क्लब के अध्यक्ष पद के चुनावों में एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। यह कार्रवाई पिछले साल के 'बार्सागेट' प्रकरण के संदर्भ में की गई। जिसमें क्लब के अधिकारियों पर आरोप लगा था कि उन्होंने उन मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों को बदनाम करने का अभियान चलाया जो क्लब और तत्कालीन अध्यक्ष बोर्टोम्यु के आलोचक थे। पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों का नाम नहीं बताया लेकिन अध्यक्ष पद के दावेदार जोआन लापोर्टा ने स्पेन की मीडिया की खबरों में पुष्टि की है कि बार्टोम्यु हिरासत में लिए गए लोगों में शामिल हैं।

पैरालंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले संदीप डोप परीक्षण से पहले हुए गायब

नई दिल्ली (एजेंसी)।

विश्व चैंपियन और तोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई कर चुके भाला फेंक के खिलाड़ी संदीप चौधरी कथित रूप से यहां ट्रेनिंग केंद्र पर प्रतियोगिता के इतर डोप परीक्षण से पहले लापता हो गए। भारतीय पैरालंपिक समिति (पीसीआई) के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। टारगेट ओलंपिक पोडिया योजना (टॉप्स) में शामिल चौधरी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर से 'भागने' से कोविड-19 महामारी को देखते हुए लागू नियमों को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं। पीसीआई अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर पीटीआई को बताया, 'जब हाल में विदेश से डोप परीक्षण करने वाले अधिकारियों की टीम संदीप द्वारा दी रहने के स्थान संबंधी जानकारी के आधार पर नमूने लेने पहुंची तो वह लापता हो गया। हो सकता है कि वह जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर से भाग गया है जहां वह ट्रेनिंग कर रहा था।' इंडोनेशिया में 2018 एशियाई पैरा खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले 24 साल के चौधरी से प्रतिक्रिया के लिए संपर्क नहीं हो पाया है। चौधरी उन तीन भारतीय पैरा एथलीटों में शामिल हैं जो अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) के पंजीकृत परीक्षण पूल का हिस्सा हैं। तोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके भाला फेंक के खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर और सुमित भी इस पूल का हिस्सा हैं। चौधरी सामान्यतः एफ-44 वर्ग में चुनौती पेश करते हैं जिनका एक पैर कटा होता है या एक या दोनों पैर में कमजोरी होती है। वे बिना कृत्रिम अंक के चुनौती पेश करते हैं। अधिकारी ने कहा, 'वह आईपीसी के आरटीपी का हिस्सा था इसलिए उसे नियमित रूप से (प्रत्येक तीन महीने में) रहने के स्थान संबंधी जानकारी देनी होती थी और रहने के स्थान संबंधी फॉर्म में दी जानकारी के आधार पर डोप परीक्षण करने वाले बिना जानकारी दिए आए थे। संभावना है कि किसी ने विदेश से डोप परीक्षण करने के लिए आने वालों की जानकारी उसे दे दी हो।' उन्होंने कहा, 'कोविड-19 के खतरे के कारण खिलाड़ियों की मूवमेंट को लेकर कड़े नियम हैं और पता नहीं चला है कि संदीप ट्रेनिंग केंद्र को छोड़कर कैसे चला गया। जब कोई खिलाड़ी शिविर में आता या जाता है तो उसे पृथकवास के नियमों का पालन करना पड़ता है।' चौधरी अगर अगले 12 महीने में दो और परीक्षण 'मिस' करते हैं तो उन्हें पहले उल्लंघन के लिए सजा दी जा सकती है और उन्हें दो साल तक के प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है।

बुमराह चोटिल नहीं, आने वाले टूर्नामेंटों के लिए लिया आराम

अहमदाबाद। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को कोई चोट नहीं है और उन्होंने आने वाले टूर्नामेंटों को देखते हुए कुछ दिनों का आराम लिया है। बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से आराम लेने की इजाजत मांगी थी जिसे बोर्ड ने स्वीकार किया था। बुमराह को लेकर अटकलें चल रही थी लेकिन पता चला है कि उन्हें चोट नहीं लगी है और उन्होंने आईपीएल, इंग्लैंड दौरे और टी20 विश्व कप को देखते हुए आराम लिया है। एक अधिकारी ने कहा, बुमराह की फिटनेस को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। वह बस कुछ समय के लिए अपने घर पर आराम करना चाहते थे और सबसे जरुरी यह है कि यह उनका निजी मामला है। बुमराह को 2019 में चोट लगी थी और वह चार महीने तक बाहर रहे थे। उन्होंने जनवरी 2020 में वापसी की और लॉकडाउन लगने के कुछ महीने पहले तक क्रिकेट खेला। लॉकडाउन के बाद बुमराह आईपीएल और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेले। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 36 ओवर गेंद करने वाले बुमराह ने तीन पारियों में सिर्फ 12 ओवर गेंदबाजी की। बुमराह दूसरे टेस्ट से बाहर रहे थे। उन्होंने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में छह ओवर और तीसरे टेस्ट की पहली पारी में छह ओवर गेंदबाजी की। तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में उन्हें गेंदबाजी करने का मौका नहीं दिया गया। इस बीच क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज से भी बाहर रह सकते हैं। बुमराह को इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 से सीरीज से आराम दिया गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच पुणे में 23 मार्च से वनडे सीरीज शुरू होनी है। बुमराह की अनुपस्थिति में भारत के पास नए खिलाड़ियों को मौका देने का अवसर रहेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चार मार्च से खेला जाएगा।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थीं यामी गौतम

बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थीं, लेकिन एक हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी को बदलकर रख दिया है। जिसको वह कभी भूल नहीं पाती हैं। वह दर्दनाक सड़क दुर्घटना से गुजर चुकी हैं। इस दुर्घटना ने उनकी पूरी जिंदगी और भविष्य को बदलकर रख दिया था। यह बात खुद यामी गौतम ने बताई है। यामी गौतम ने हाल ही में अंग्रेजी वेबसाइट बॉम्बे टाइम्स को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने फिल्म करियर के अलावा निजी जिंदगी के बारे में हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। यामी गौतम ने खुलासा किया है कि एक सड़क दुर्घटना में उनकी गर्दन पर लगी चोट ने एक ही पल में उनकी पूरी जिंदगी को बदलकर रख दिया। हालांकि इस बारे में यामी गौतम ने पिछले साल अगस्त में भी सोशल मीडिया के जरिए बताया था, लेकिन अब उन्होंने इस चोट के बारे में विस्तार से बात की है। यामी गौतम ने अपने इंटरव्यू में कहा, 'यह एक सुबह की बात है, जब मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकली थी। मैं अपने टू व्हीलर से हाईवे पर थी। मेरे आगे चल रही एक कार ने गलत सिग्नल दिया। ड्राइवर ने दाईं तरफ मुड़ने का सिग्नल दिया था, लेकिन उसने अपनी कार बाईं ओर मोड़ ली थी। मैं टक्कर खाकर गिर पड़ी, जबकि कार ड्राइवर एक पल भी रुके बिना वहां से भाग गया। अभिनेत्री ने आगे कहा, 'शुक्र है कि मैंने हेल्मेट पहन रखा था। मैं हिल भी नहीं पा रही थी, आसानी से मैं किसी गाड़ी के नीचे आ सकती थी। हालांकि, एक शख्स ने मेरी मदद की और मैं जैसे-तैसे खड़ी हो पाई। यह दुर्घटना सर्दियों के समय में हुई थी। इस मौसम में उत्तर भारत के लोग काफी कपड़े पहना करते हैं। शुक्र है कि मैंने ढेर सारे कपड़े पहन रखे थे, जिसने मुझे बाहरी चोट से बचा लिया था। बाहर से मुझे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन मैं इंटरनल इंजरी का शिकार हो चुकी थी।' यामी गौतम ने आगे कहा, 'डॉक्टर ने बताया कि मेरी गर्दन में फ्रैक्चर है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मैं कभी लाइफ में वर्कआउट नहीं कर सकूंगी और तब मैं आईएएस ऑफिसर बनने का ख्वाब देख रही थी।' अभिनेत्री ने बताया कि उनके गर्दन का दर्द अभी भी उन्हें परेशान करता है। उन्होंने कहा, '5 इंच की हील पहन कर इधर-उधर ज्यादा घूम लूं कि तुरंत दर्द बढ़ जाता है।' गौरतलब है कि यामी गौतम ने पिछले साल लॉकडाउन में अपनी गर्दन के दर्द के निजात पाने के लिए काफी योगा भी किया था। उन्होंने योगा करते हुए अपनी एक तस्वीर साझा कर इस चोट के बारे में भी बताया था। हालांकि, योगा करने से यामी गौतम को काफी फायदा हुआ है। उनका मानना है कि वह अब पहले से कार्फ बेहतर महसूस करती हैं। आपको बता दें कि यामी गौतम इन दिनों अपनी कई फिल्मों को लेकर सुर्खियों में हैं। वह जल्द ही भूत पुलिस और दसवीं में नजर आने वाली हैं।

टाइगर श्रॉफ के बर्थडे पर आया हीरोपंती 2 का पोस्टर

टाइगर श्रॉफ आज (2 मार्च) को अपना बर्थडे मना रहे हैं। इस दिन उनकी आगामी फिल्म का पोस्टर और रिलीज डेट आ जाए तो इससे बेहतर तोहफा उनके फैंस के लिए और क्या हो सकता है। टाइगर श्रॉफ ने 'हीरोपंती' के जरिये बॉलीवुड में कदम रखा था। यह फिल्म उनके दिल में खास स्थान रखती है। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी और टाइगर तथा कृति सेनन ने फिल्मों में अपनी जगह और पहचान बना ली। इसी फिल्म का दूसरा भाग आ रहा है जिसका पोस्टर रिलीज हुआ है। फिल्म का नाम है 'हीरोपंती 2'। पोस्टर में सूटेड-बूटेड टाइगर दोनों हाथ में गन लिए ऊंची बिल्डिंगों के बीच कार पर खड़े एक्शन करते नजर आ रहे हैं। उनकी यह अदा फैंस को दीवाना कर रही है। इस फिल्म के निर्माता साजिद नाडियाडवाला है। पोस्टर पर निर्देशक के रूप में अहमद खान और लेखक के रूप में रजत अरोरा का नाम है। साथ में रिलीज डेट है 3 दिसम्बर 2021, खास बात यह है कि यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

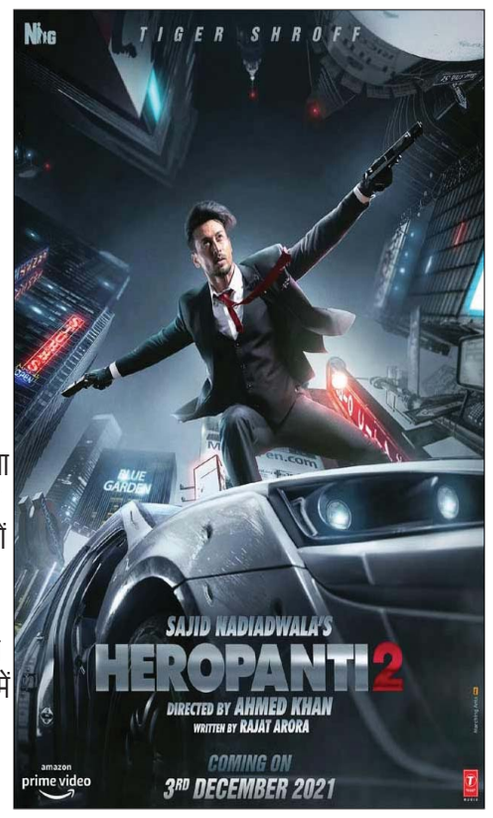

अहान शेट्टी की मूवी 'तड़प' का पोस्टर रिलीज, अक्षय और अजय ने किया वेलकम

साजिद नाडियाडवाला की नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के साथ डेब्यू करना हर एक्टर का सपना होता है और 'तड़प' अहान शेट्टी के लिए एक बड़ा डेब्यू है। अहान के रूप में एक यंग डायनामिक पर्सनालिटी फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखने के लिए तैयार है। अहान को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में भी हलचल है। फिल्म उद्योग के दो दिग्गज अक्षय कुमार और अजय देवगन जो इससे पहले साजिद नाडियाडवाला के साथ सहयोग कर चुके है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर नई एंट्री का स्वागत किया है। फिल्म का पोस्टर बेहद प्रॉमिसिंग लग रहा है। इस फ़िल्म में अहान शेट्टी के अपोजिट खूबसूरत तारा सुतारिया नज़र आएंगी, जिन्होंने दो साल पहले शोबिज़ में एंट्री ली थी और कुछ ही समय में अपने समकालीनों के बीच खुद के लिए जगह बना ली। अहान शेट्टी और तारा सुतारिया की एक नई जोड़ी के साथ एक प्रेम कहानी सबसे रोमांचक तरीके से सुलझने का इंतज़ार कर रही है जो दर्शकों के लिए एक ट्रीट होगी। साजिद नाडियाडवाला के साथ अहान शेट्टी की शुरुआत विरासत को आगे बढ़ाने जैसा है क्योंकि सुनील शेट्टी को भी निर्माता द्वारा लॉन्च किया गया था और वह फिर से अपना योगदान देते हुए धन्य और उत्साहित महसूस करत रहे हैं। अहान के पहले लुक ने दर्शकों के बीच उत्साह की एक विशाल लहर पैदा कर दी है और सिल्वर स्क्रीन पर एक नए चेहरे को देखना दर्शकों के लिए टेस्टिंग टाइम होगा। फिल्म मिलन लथुरिया द्वारा निर्देशित है, जिसमें अहान शेट्टी, तारा सुतारिया, सौरभ शुक्ला, कुमुद मिश्रा और सुमित गुलाटी नज़र आएंगे। फिल्म का निर्माण साजिद नाडियाडवाला कर रहे हैं और फॉक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा सह-निर्मित है जो रजत अरोड़ा द्वारा लिखित है और फिल्म में म्यूजिक प्रीतम द्वारा दिया गया है। 'तड़प' 24 सितम्बर 2021 को रिलीज होगी।

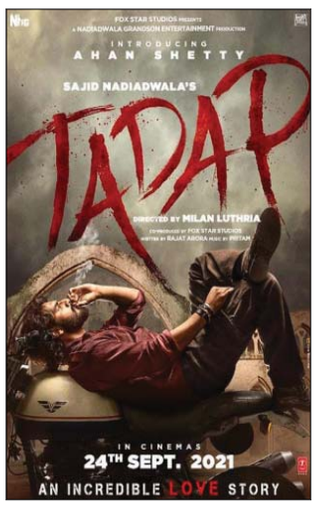

शो की लाइन बोलते हुए चीखने लगे कार्तिक आर्यन

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की अगली फिल्म धमाका का टीज़र रिलीज़ हो गया है। यह एक समाचार चैनल के कामकाज में एक झलक पेश कर रहा है। राम माधवानी द्वारा निर्देशित फिल्म में कार्तिक ने एक प्राइम टाइम न्यूज़ एंकर की भूमिका निभाई है। टीजर में एक सिचुएशन को दिखाया गया है जिसमें एक शो के लिए कार्तिक आर्यन को संघर्ष करते देखा गया है। किसी खबर को सुनने के बाद कार्तिक आर्यन काफी ज्यादा परेशान हो गये हैं। वह इस शो को करने की हालत में नहीं है लेकिन शो की टीम उन्हें लगातार पुश कर रही है शो करने के लिए। कैमरा हैडल करने वाली महिला कार्तिक आर्यन को कहती है कि ये शो तुमने शो शुरू किया है तुम्ही खत्म करो, जिसके बाद कार्तिक थोड़ा नॉर्मल होते हुए नजर आते हैं। टीजर को देखकर आप समझ सकते हो कि एंकर कार्तिक को अपने भविष्य के कैरियर और उसमें मानवतावादी के बीच चयन करना होगा। धमाका जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली है।

टीजर में क्या दिखाया

धमाका के टीज़र में, अर्जुन पाठक (कार्तिक आर्यन) अपनी अंतरात्मा से लड़ते हुए दिखाई दे रहे है क्योंकि वह एक बहुत भयानक स्थिति में फंस जाते है। उन्हें अपने करियर और उसमें मानवतावादी के बीच चयन करना होगा। अर्जुन अपनी लाइनों के साथ संघर्ष कर रहा है और चालक दल को कैमरे बंद करने के लिए कह रहा है। तब अमृता सुभाष उसे अपना काम करने के लिए प्रेरित करती है और उसे बताती है कि इस शो को चलना चाहिए। यह कहने के बाद कि वह ऐसा नहीं कर सकता, अर्जुन ने अंततः अपनी नौकरी फिर से शुरू कर दी और अपनी पंक्तियाँ कह दीं।

कार्तिक आर्यन ने शेयर किया टीजर

धमाका का टीज़र शेयर करने के लिए कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम का सहारा लिया। टीज़र को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 卐 मैं हूं अर्जुन पाठक, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। धमाका जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। साथ ही कार्तिक ने टीजर का वीडियो भी शेयर किया है।

फिल्म के बारे में जानकारी

धमाका एक न्यूज़ चैनल के काम पर आधारित फिल्म है। कार्तिक आर्यन एक प्राइम टाइम न्यूज़ एंकर की भूमिका में नज़र आएंगे। फिल्म को रिकॉर्ड 10 दिनों में कोरोनावायरस महामारी के दौरान मुंबई में शूट किया गया है। फिल्म की शूटिंग से पहले फिल्म के चालक दल ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था जिसके बाद यह सभी 14 दिन के लिए एक होटल में क्वारंटाइन हुए थे। 14 दिन बाद पूरी टीम ने फिल्म की शूटिंग शुरू की थी। धमाका का निर्माण रॉनी स्क्रूवाला की आरएसवीपी और राम माधवानी फिल्म्स (सह-निर्माता अमिता माधवानी के साथ) द्वारा किया गया है। पिछले साल कार्तिक आर्यन के जन्मदिन के अवसर पर 22 नवंबर को फिल्म की घोषणा की गई थी।

'राधेश्याम' में प्रभास के लवरबॉय अवतार को देख लड़कियां हुईं दीवानी

फिल्म 'राधेश्याम' में प्रभास को अपने दशक पुराने लवरबॉय अवतार में लौटते देखा जा सकता है। बहुत सारी एक्शन फिल्में करने के बाद वह एक दशक के बाद रोमांटिक रूप में लौट रहे हैं। राधेश्याम में इस लवरबॉय रूप में वापसी से उनके फैंस खासकर लड़कियों पर दीवानापन छा गया है। सोशल मीडिया पर प्रभास की प्रशंसक लड़कियां उनके प्यार में पागल हो रही हैं। राधेश्याम, जो 30 जुलाई 2021 को रिलीज़ के लिए तैयार है, हाल ही में फिल्म का टीज़र सामने लाया है और तब से लड़कियों को प्रभास के अवतार से मन नहीं भर पाया है। सोशल मीडिया 'मेरी जान', 'लव यू', '30 जुलाई का इंतजार है' और इस तरह की अन्य टिप्पणियों से भर के बह रहा है। प्रभास का स्टारडम ऐसे ट्रीटमेंट के लिए नया नहीं है क्योंकि पोस्टर 1 और 2 रिलीज होने पर उनके महिला प्रशंसकों से इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आयी थीं। एक पोस्टर में वह अपने पुरानेवाले लवरबॉय के अवतार में और दूसरे में बिलकुल चॉकलेट बॉय लग रहे थे। पिछले दशक में हम ने प्रभास को एक्शन मूवी में देखा है और उनकी फिल्मों के साथ उनके फैंस के प्यार और समर्थन की वजह से वह नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। अभिनेता अब एक व्यस्त व्यक्ति है क्योंकि बहुत सारे फिल्म निर्माता उनके साथ काम करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते उनकी फिल्म सालार को रिलीज़ डेट की घोषणा कर दी गई थी और उनके प्रशंसकों से ढेरों क्रेज़ी प्रतिक्रियाँए प्राप्त हुई थी। प्रभास के पास वर्तमान में 4 पैन-इंडिया फिल्में हैं और उन्होंने अपना लॉकडाउन परियोजनाओं को पढ़ने और साइन करने में खर्च किया था। आदिपुरुष, राधेश्याम, सलार और दीपिका पादुकोण के साथ अनटाइटल्ड, सभी फिल्में पैन-इंडिया प्रोजेक्ट है। वह अपनी आगामी परियोजनाएं जैसे कि पौराणिक कथाओं, रोमांटिक ड्रामा, साय-फाई और सालार की अनरीविल्ड शैली के साथ विभिन्न शैली की फिल्मों में अभिनय करेंगे।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कानून की पढ़ाई कैसे करें ? वकालत करने के लिए जानें बेसिक बातें

सामान्य रूप से लॉ की पढ़ाई के लिए आपका 12वीं पास होना आवश्यक है और यह किसी भी विषय में हो सकता है। इसमें 50 परसेंट मार्क्स ही आवश्यक है और ऐसे में आपकी एज 20 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में कानून का शासन है। हर चीज कानून के अनुसार चलती है। कानून के अनुसार ही प्रशासन चलता है, कानून के अनुसार ही अदालतों का सिस्टम चलता है।

अदालतों में हम देखते हैं कि कानून के अनुसार ही एक पक्ष दूसरे पक्ष को चुनौती देता है और अदालतों में कानून के जानकार इसके भिन्न पक्षों की व्याख्या भी करते हैं। इन्हीं कानून के जानकारों को हम वकील कहते हैं और वकील बनने के लिए आपको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ती है। इस पढ़ाई का का प्रथम चरण होता है एलएलबी का, यानी बैचलर आफ लॉ! वैसे कानून की पढ़ाई सिर्फ एक प्रोफेशन भर ही नहीं है, बल्कि यह उन तमाम जरूरतमंद लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ने में एक अति महत्वपूर्ण कड़ी है, जो तमाम कारणों से अन्याय के शिकार होते हैं। जिन्हें पता तक नहीं होता है कि उन्हें कानून की जानकारी ना होने के कारण असीमित नुकसान उठाना पड़ा है। सच कहा जाए तो हमारे देश में ला प्रोफेशनल्स की जवाबदेही, किसी भी दूसरे प्रोफेशन से अधिक हो जाती है, क्योंकि यह कानून के शासन पर भरोसा पैदा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

सामान्य रूप से लॉ की पढ़ाई के लिए आपका 12वीं पास होना आवश्यक है और यह किसी भी विषय में हो सकता है। इसमें 50 परसेंट मार्क्स ही आवश्यक है और ऐसे में आपकी एज 20 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको सीएलएटी (एख्रइट्ठ) एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जिसे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट कहा जाता है और यह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। एग्जाम में आपसे लॉजिकल रीजनिंग, लीगल, एटीट्यूड, गणित, अंग्रेजी और जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद 5 साल के कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। सामान्यत : पांच साल के इन्टीग्रेटेड कोर्स के एंट्रेंस हेतु 200 अंकों के क्वेश्चन पेपर के लिए डेढ़ घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें इंग्लिश के 30 अंक, सामान्य ज्ञान के 50 अंक, लीगल एप्टीट्यूड के 20 अंक, लीगल रीजनिंग के 20 अंक होते हैं एवं 30 अंकों का एक एस्से भी लिखना होता है।

लॉ करने के बाद आपको इंटर्नशिप का कोर्स करना होता है और इस दौरान आपको काफी कुछ ट्रेनिंग मिलती है। इंटर्नशिप के बाद आपको किसी भी राज्य के स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना होता है और उसके बाद ऑल इंडिया बार कौंसिल का एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल जाता है और इसके बाद आप वकील बन जाते हैं।

हालाँकि, ग्रेजुएशन के बाद भी आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं और तब यह मात्र 3 साल का होता है। ग्रेजुएशन में भी आपको साधारणतया 50 परसेंट मार्क्स लाना होता है। वैसे एससी/एसटी कटगरी स्टूडेंट्स के लिए इसमें छूट भी होती है।

लॉ की केटेगरी देखें तो मुख्यत : कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, पेटेंट, एटर्नी, फैमिली लॉ, साइबर लॉ और बैंकिंग ला के रूप को गिनाया जा सकता है और किसी भी विषय में बाद में आप खुद को स्पेशलाइज कर सकते हैं। जैसा कि नाम के साथ ही स्पष्ट है कि पर्टिकुलर फील्ड में आप सम्बंधित क्षेत्र की विशेषज्ञता की हद तक जानकारी लेंगे।

खास बात यह भी है कि एलएलबी के बाद एलएलएम और पीएचडी जैसी विशेषज्ञता भी आप हासिल कर सकते हैं और बाद के दिनों में आप न्यायपालिका की परीक्षा देकर जज बनने की भी कोशिश कर सकते हैं।

लॉ करने के लिए देश भर के कुछ अच्छे कॉलेजों की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल, द वेस्ट बेंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्युरीडिकल साइंस, कोलकाता, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ, राजीव गाँधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लागल स्टडीज, कोच्चि का नाम मुख्य रूप से गिनाया जा सकता है। यूं अधिकांश यूनिवर्सिटीज में यह कोर्स उपलब्ध हैं और देश के तमाम जिलों में आपको ऐसे कॉलेज मिल जायेंगे, जहाँ से आप लॉ में एडमिशन लेकर कानून की समझ बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में इस कोर्स के स्कोप की बात करने की जरुरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल अदालती प्रैक्टिस के अलावा कॉरपोरेट वर्ल्ड में, एनजीओ में, बैंकिंग सेक्टर में, सरकार एवं उसके संस्थानों में, स्वतंत्र पत्रकारिता (फ्रीलांस जर्नलिज्म) में, सेना तक में, लॉ फर्म्स के साथ-साथन्यायिक सेवा तक में इसका विस्तार है।

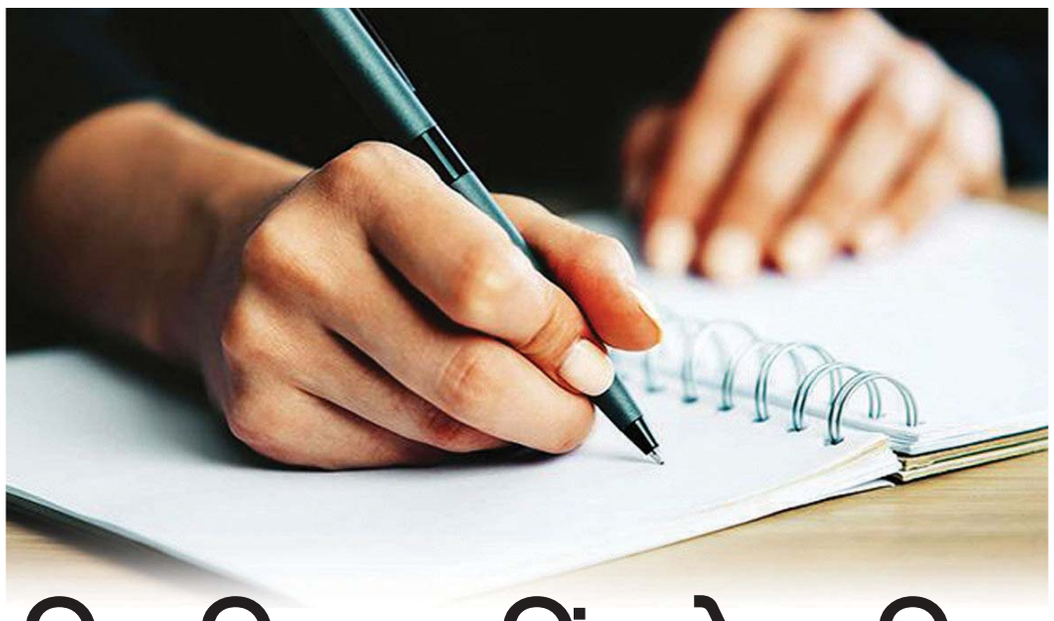

क्रिएटिव राइटिंग के जरिए बनाएं लेखन के क्षेत्र में कॅरियर

रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में किसी औपचारिक शिक्षा की विशेष आवश्यकता नहीं है। आपकी कल्पना, अवलोकन और रचनात्मकता के साथ लिखने की क्षमता ही आपके भविष्य के मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि अंग्रेजी साहित्य या पत्रकारिता और संचार में एक शैक्षिक पृष्ठभूमि आपके कॅरियर की राह को आसान बनाती है।

ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जिन्हें लिखना बहुत पसंद होता है। लेखन की कई विधाएं हैं, इन्हीं में से एक है क्रिएटिव राइटिंग। लेखन के क्षेत्र की यह विधा बेहद कलात्मक है। इस क्षेत्र से जुड़े लोग वास्तव में रचनात्मक लेखक हैं, जिन्हें लोग उपन्यासकार, कवि, गीतकार आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। क्रिएटिव राइटर्स के पास लेखन में जादुई शक्ति होती है और अपने काम के माध्यम से, वे पाठकों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें परेशान, घृणित, मंत्रमुग्ध या खुश कर सकते हैं। आमतौर पर लोग इस काम को आसान मानते हैं, जबकि लेखन बनाना एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें बहुत अधिक शोध और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर आप भी लेखन में अपनी रूचि रखते हैं तो इस क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा सकते हैं

क्या है क्रिएटिव राइटिंग

रचनात्मक लेखन वह लेखन है जिसमें एक लेखक का उद्देश्य गद्य और काव्य छंदों के माध्यम से अपनी भावनाओं, भावनाओं, कल्पनाशील विचारों और विचारों को व्यक्त करना है। विभिन्न तरह के लेखन जैसे उपन्यास, कविता, कहानी, नाटक, आत्मकथा, पटकथा लेखन, कॉपी लेखन आदि को रचनात्मक लेखन कहा जाता है। रचनात्मक लेखन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक दुनिया के चित्र बनाने के लिए बहुत अधिक कल्पना, अवलोकन और एक जन्मजात क्षमता की आवश्यकता होती है। विभिन्न विषयों और शैलियों पर लेख पढ़कर एक अच्छा लेखक बन सकता हैय हर तरह से जीवन का अनुभव करना और बहुत सारे मुहावरों, लहजों और स्थानीय भावों को सीखना और सुनना। वैसे तो क्रिएटिव राइटिंग कुछ लोगों को जन्मजात उपहार में मिलती हैं, लेकिन रचनात्मक लेखन में कोर्स करके कोई भी अपने लेखन कौशल में सुधार कर सकता है।

योग्यता

कॅरियर एक्सपर्ट कहते हैं कि रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में किसी औपचारिक शिक्षा की विशेष आवश्यकता नहीं है। आपकी कल्पना, अवलोकन और रचनात्मकता के साथ लिखने की क्षमता ही आपके भविष्य के मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि अंग्रेजी साहित्य या पत्रकारिता और संचार में एक शैक्षिक पृष्ठभूमि आपके कॅरियर की राह को आसान बनाती है। वैसे भारत में कुछ संस्थान रचनात्मक लेखन में शार्ट टर्म कोर्स कराते हैं और इन पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकंडरी या 10+2 होनी चाहिए। इन पाठ्यक्रमों की न्यूनतम अवधि एक वर्ष है।

व्यक्तिगत गुण

कॅरियर एक्सपर्ट कहते हैं कि एक क्रिएटिव राइटर को कल्पनाओं के आकाश में विचरने के साथ-साथ उसे कागज पर भी बेहतरीन तरीके से उतारने की कला आनी चाहिए। इसके अलावा उसके भीतर पढ़ने व नई चीजों को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, ताकि वह अपने शब्दकोश को अधिक मजबूत बना सके। चूंकि इन दिनों लेखन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने लगता है। इसलिए उसे कंप्यूटर का ज्ञान होना व इंटरनेट में आवश्यक सामग्री खोजने की कला आनी चाहिए। इसके अलावा उसके भीतर ऑर्ब्जवेशन स्किल्स व कम्युनिकेशन स्किल्स भी मजबूत होने चाहिए। क्योंकि जब एक लेखक अपने या दूसरों के अनुभवों के पन्ने पर उतारता है तो उसका एक अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन के जरिए उसके लेखन में भी विविधता को आसानी से देखा जा सकता है।

संभावनाएं

क्रिएटिव राइटर्स के पास अवसरों की कोई कमी नहीं है। कॅरियर एक्सपर्ट की मानें तो आप अपनी रूचि के अनुसार उपन्यास से लेकर संस्मरण, कविता, गीत, साइंस फिक्शन, रोमांस, स्क्रिप्ट, नाटक, यात्रा-वृत्तांत आदि लिख सकते हैं। इसके अलावा आप पत्र-पत्रिकाओं और समाचार पत्रों आदि के लिए रिपोर्ट, साक्षात्कार, सुविधाएँ, आलोचना और समीक्षाएं लिख सकता है। इसके अलावा, रचनात्मक लेखक वेब साइटों के लिए भी कंटेंट लिख सकते हैं या प्रिंट मीडिया के लिए लेख बना सकते हैं। आप किसी एक संस्थान से जुड़कर काम कर सकते हैं या फिर अलग-अलग संस्थानों के लिए फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं।

आमदनी

इस क्षेत्र में आमदनी आपके अनुभव व कौशल पर निर्भर करती हैं। शुरूआती दौर में एक क्रिएटिव राइटर आठ से दस हजार रूपए प्रतिमाह कमा सकता है। इसके बाद अनुभव बढ़ने के बाद आपका काम व आमदनी दोनों बढ़ती चली जाती है।

प्रमुख संस्थान

इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
डॉ.बाबासाहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मीडिया स्टडीज, अहमदाबाद
कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी

बेहद अलग है जूलॉजी में कॅरियर

जूलॉजी में कॅरियर बनाने के लिए आपको सबसे पहले जीव विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान में ज्ञान प्राप्त करना होगा। 12वीं के बाद बैचलर की डिग्री हासिल करने के बाद आप इस क्षेत्र में कदम बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग है, जो प्रकृति में मौजूद विभिन्न तरह के प्राणियों के बारे में गहराई से जानने की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोग जूलॉजी में अपना करियर देख सकते हैं। जूलॉजी, जीव विज्ञान की एक शाखा है, जो मछली, सरीसृप, पक्षियों और स्तनधारियों सहित जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह संरचना, शरीर रचना, विशेषताओं, व्यवहार, वितरण, पोषण की विधि, शरीर विज्ञान, आनुवंशिकी और पशु प्रजातियों के विकास को शामिल करता है। जूलॉजी का अध्ययन करते समय आप समुद्री जीवों, चिड़ियाघर के जानवरों और जंगली और यहां तक कि घरेलू पालतू जानवरों सहित जानवरों के जीव विज्ञान और आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। ऐसे में अगर आप भी इनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो बतौर जूलॉजिस्ट बनकर ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में

क्या होता है काम

एक जूलॉजिस्ट का मुख्य काम जानवरों के व्यवहार, विशिष्ट विशेषताओं और उनमें विकासवादी प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजिस्ट को पशु जीवविज्ञानी या वैज्ञानिक भी कहा जाता है। यह एक बेहद विस्तृत क्षेत्र है और विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले जूलॉजिस्ट को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। मसलन, पक्षियों के अध्ययन में विशेषज्ञता वाले जूलॉजिस्ट्स को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है, वहीं मछली का अध्ययन करने वाले को आइकथोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक इसी तरह, जो जूलॉजिस्ट्स जो उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं उन्हें हेरपेटोलॉजिस्ट नाम से जाना जाता है और स्तनधारियों से जुड़े लोगों को मैमलॉजिस्ट कहा जाता है। उनके कार्यक्षेत्र में जानवरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीड़े, मछलियों और कीड़े के पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार करना और उन्हें विभिन्न स्थानों पर प्रबंधित करना है। जूलॉजिस्ट डीएनए पहचान सहित उच्च तकनीक के सभी प्रकार के क्षेत्र में और प्रयोगशाला में काम करते हैं, और वे जानकारी के डेटाबैंक विकसित करते हैं।

योग्यता

कॅरियर एक्सपर्ट की मानें तो जूलॉजी में कॅरियर बनाने के लिए आपको सबसे पहले जीव विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान में ज्ञान प्राप्त करना होगा। 12वीं के बाद बैचलर की डिग्री हासिल करने के बाद आप इस क्षेत्र में कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि आप इस क्षेत्र में बैचलर की डिग्री के बाद मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं।

व्यक्तिगत कौशल

एजुकेशन एक्सपर्ट कहते हैं कि जूलॉजी के क्षेत्र में कॅरियर देख रहे छात्रों का बेहद साहसी होना जरूरी है और उनके जीवन में डर के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें समर्पित, स्वतंत्र और मेहनती भी होना चाहिए। उन्हें विभिन्न लोगों के साथ काम करना आना चाहिए। चूंकि वैज्ञानिक अक्सर शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उनके पास प्रभावी लिखित और मौखिक संचार क्षमताएं होनी चाहिए। वह अपना अधिकांश समय जानवरों के साथ बिताते हैं, इसलिए उन्हें जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें काटने, खरोंचने आदि जैसे हमलों के लिए हरदम मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और चोटों को सहने की क्षमता होनी चाहिए। जूलॉजी के क्षेत्र में आपको कई घंटों तक काम करना पड़ सकता है, जो वास्तव में आपके लिए थकाऊ हो सकता है।

संभावनाएं

बतौर जूलॉजिस्ट आप चिड़ियाघर, वाइल्डलाइफ सर्विस, बोटेनिकल गार्डन, कंसर्वेशन आर्गेनाइजेशन, नेशनल पार्क, यूनिवर्सिटी व लेबोरेटरीज आदि में काम कर सकते हैं। जहां चिड़ियाघर व म्यूजियम में वे बतौर एजुकेटर या क्यूरेटर अपना कॅरियर आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं आप स्कूल या कॉलेज में टीचर्स या रिचर्सर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। वहीं अपना शोध पूरा कर लेने के बाद आप एक स्वतंत्र शोधकर्ता के रूप में भी आगे कार्य कर सकते हैं। इसी तरह एनिमल रिहैबिलिटेटर्स या बतौर कंसर्वेशनिस्ट भी आप अपना उज्जवल भविष्य देख सकते हैं।

आमदनी

इस क्षेत्र में आपका वेतन शिक्षा, अनुभव, कार्य की प्रकृति व स्पेशलाइजेशन के आधार पर निर्भर करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छी आमदनी हो सकती है। शुरूआती दौर में आप 10000 से 15000 रूपए महीना आसानी से कमा सकते हैं। वहीं कुछ समय के पश्चात आपकी आमदनी 25000 रूपए प्रतिमाह या इससे अधिक भी हो सकती है। अगर कुछ वर्षों के अनुभव के पश्चात आप विदेश में काम करते हैं तो आप यकीनन लाखों में कमा सकते हैं।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

बाइडेन प्रशासन देगा चीन को झटका, अमेरिकी संसद में पेश हुआ यह विधेयक

वाशिंगटन। रिपब्लिकन पार्टी के दो सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया है, जिसमें अमेरिका से ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध बहाल करने और पुरानी हो चुकी एवं अनुत्पादक 'एक-चीन' की नीति को रद्द करने की अपील की गई है। सांसद टॉम टिफनी और स्कॉट पेरी ने यह विधेयक पेश किया है, जिसमें बाइडन प्रशासन से अंतरराष्ट्रीय संगठनों में ताइवान की सदस्यता को समर्थन देने और अमेरिका एवं ताइवान के बीच मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए ताइपे के साथ वार्ता करने की अपील की गई है। टिफनी ने कहा, ''पिछले करीब 40 साल से अमेरिका में दोनों दलों के राष्ट्रपतियों ने बीजिंग के इस झूठ को कई बार दोहराया है कि ताइवान साम्यवादी चीन का हिस्सा है, जबकि वास्विक सच्चाई इसके विपरीत है। इस पुरानी हो चुकी नीति को बदलने की आवश्यकता है।'' अमेरिका के 1979 तक ताइवान की सरकार के साथ सामान्य राजनयिक संबंध थे, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने ताइपे के साथ औपचारिक संबंध अचानक समाप्त कर दिए और चीन में साम्यवादी शासन को मान्यता दी। चीन ताइवान को विद्रोही प्रांत मानता है और वह उसे फिर से मुख्य भूमि में शामिल करना चाहता है।

पाकिस्तान में दर्दनाक हादसा, बारूदी सुरंग में विस्फोट में दो बच्चों की मौत

पेशावर (पाकिस्तान)। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में सोमवार को बारूदी सुरंग में विस्फोट में दो बच्चों की मौत हो गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना अफगानिस्तान की सीमा से सटे अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दक्षिण वजीरीस्तान कबायली जिले की शावल घाटी में हुई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री महमूद खान ने दोनों बच्चों की मौत पर शोक और दुख जताया है। विस्फोट में मारे गये दोनों बच्चे भाई-बहन थे, जिनकी उम्र 12 वर्ष और आठ वर्ष थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शांति एवं सौहार्द बनाये रखने के लिए कबायली लोगों का बलिदान लंबे समय तक याद किया जाएगा।

कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के लिए नेपाल ने भारत से लगाई मदद की गुहार

काठमांडू। नेपाल सात मार्च से 55 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविड- रोधी टीकाकरण अभियान की शुरू करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही देश भारत से टीके की 20 लाख खुराक खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री हृदयेश त्रिपाठी ने रविवार को मीडिया को बताया कि टीके में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। नेपाल सरकार ने भारत सरकार से कोविशील्ड टीके की 10 लाख खुराकें ली थीं। सरकार भारत से कोविशील्ड की 20 लाख और खुराक खरीद रही है। इसी तरह चीन ने भी नेपाल को टीके की पांच लाख खुरा दान देने की पेशकश की है। नेपाल ने अपने कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान की सफल शुरुआत की है, लेकिन अधिकारियों को भविष्य की आपूर्ति को लेकर चिंता है। त्रिपाठी ने कहा, दुनियाभर में मुट्ठी भर कंपनियों से टीके की बहुत मांग की जा रही है और हम सूची के अंत में हो सकते हैं। उन्होंने कहा, अबतक हम राजनीतिक और प्रशासनिक मदद से भारत से टीका ले पाएं हैं। मैं अब बहुत चिंतित हूं। मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय अधिकारी अपने छोटे से उत्तरी पड़ोसी की एक बार फिर मदद करेंगे। उन्होंने कहा, हम कंपनियों से सामान्य व्यापारिक सौदा करके टीका हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी प्रतिस्पर्धा दर्जनों अन्य देशों से है। इसलिए हमें (भारत) सरकार के प्रभाव की जरूरत है। नेपाल में कोरोना वायरस के 2,74,216 मामले सामने आए हैं और 2,777 लोगों की मौत हुई है।

भारत को निशाना बना रही है चीनी हैकर, अमेरिकी सांसद ने बाइडेन प्रशासन से की यह अपील

वाशिंगटन।अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद ने चीनी हैकरों द्वारा भारत की पावर ग्रिड प्रणाली को निशाना बनाने संबंधी रिपोर्ट के मद्देनजर सोमवार को बाइडेन प्रशासन से भारत का साथ देने का अनुरोध किया। साइबर हमले जैसी गतिविधियों की निगरानी करने वाली एक अमेरिकी कंपनी की रिपोर्ट में भारत की पावरग्रिड प्रणाली को निशाना बनाने की बात सामने आयी है। सांसद फ्रैंक पैलोन ने सोमवार को ट्वीट किया, ''अमेरिका को निश्चित रूप से हमारे रणनीतिक साझेदारों के साथ खड़ा रहना चाहिए और भारत के पावर ग्रिड पर चीन के खतरनाक साइबर हमले की निंदा करनी चाहिए, जिसकी वजह से महामारी के दौरान अस्पतालों को जनरेटरों का सहारा लेना पड़ा'' पैलोन ने ट्वीट किया, ''हम चीन को बल प्रयोग और डर के माध्यम से क्षेत्र में प्रभुत्व कायम करने की अनुमति नहीं दे सकते।'' इससे एक दिन पहले ही अमेरिका में मैसाचुसेट्स की कंपनी 'रिकॉर्डेड फ्यूचर' ने अपने हालिया अध्ययन में दावा किया कि भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के दौरान चीन सरकार से जुड़े हैकरों के एक समूह ने ''मालवेयर'' के जरिए भारत की पावरग्रिड प्रणाली को निशाना बनाया। आशंका है कि पिछले साल मुंबई में बड़े स्तर पर बिजली आपूर्ति ठप होने के पीछे शायद यही मुख्य कारण था। 'रिकॉर्डेड फ्यूचर' ने अपनी हालिया रिपोर्ट में चीन के समूह 'रेड इको' द्वारा भारतीय ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाए जाने का जिक्र किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस रिपोर्ट से अवगत है।

म्यांमार : तख्तापलट के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े

यांगून। (एजेंसी)।

म्यांमार में पिछले महीने हुए सैन्य तख्तापलट के खिलाफ मंगलवार को प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने एक बार फिर आंसू गैस के गोले छोड़े और रबर की गोलियां चलायीं। प्रदर्शनकारी पुलिस कार्रवाई के बाद फिर से एकत्रित हुए। म्यांमा के प्राधिकारियों ने हाल के दिनों में विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि उसका मानना है कि रविवार को सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कम से कम 18 लोग मारे गए थे। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने मंगलवार को इस संकट पर चर्चा के लिए बैठक की। कार्रवाई के बावजूद प्रदर्शनकारियों का बड़ी संख्या में सड़कों पर जमा होना जारी है। प्रदर्शनकारी उन्हें तितर-बितर करने के प्रयासों का अधिक कड़ाई से विरोध करने लगे हैं। म्यांमा के सबसे बड़े शहर यांगून में सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हुए जिसमें से कई ने निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले हेल्मेट पहने हुए थे। वहां एक दिन पहले पुलिस ने कई बार आंसू गैस के गोले दागे थे। उन्होंने बैरिकेड बनाने के लिए बांस और मलबे का इस्तेमाल किया और नारे लगाए। पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जाने पर प्रदर्शनकारी भाग जाते थे लेकिन जल्द ही अपने बैरिकेड पर एकत्रित हो जाते थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में उत्तरी यांगून के इंसेन इलाके में इसी तरह के अराजक दृश्य दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने दक्षिणपूर्वी म्यांमा के एक छोटे शहर दावी की सड़कों पर मार्च किया,इस दौरान वे झंडे और बैनर लिये हुए थे। प्रदर्शनकारियों के एक समूह को सुरक्षा बलों द्वारा निशाना बनाया गया क्योंकि यह समूह रविवार की कार्रवाई में मारे गए एक व्यक्ति के घर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक संकरी गली में घुस रहा था। एक अन्य समूह पर शहर के मध्य में मुख्य सड़क पर हमला किया गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार यांगून और दावी उन शहरों में हैं जहां सुरक्षा बलों ने रविवार को कथित रूप से भारी मात्रा में गोलाबारी की। ऐसी सूचना है कि उन्होंने मंगलवार को भी गोलीबारी की लेकिन तुरंत इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। संयुक्त राष्ट्र की म्यांमा पर विशेष दूत क्रिस्टीन श्रैनर बर्गनर ने सीएनएन से एक साक्षात्कार में कहा, ''मैं म्यांमा के लोगों से इस जाल में न पड़ने की अपील करता हूं, इसलिए वे शांतिपूर्ण रहें।'' उन्होंने साथ ही यह स्वीकार किया कि उनके लिए प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अपील करना आसान है। उन्होंने प्राधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे सड़कों पर लोगों को और भड़काने के लिए हिरासत में लोगों की स्थितियों के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। म्यांमा में एक फरवरी को सेना ने तख्तापलट करके देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली।

व्हाइट हाउस में एक और भारतीय-अमेरिकी की हुई बड़े पद पर नियुक्ति

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय-अमेरिकी माजू वर्गीज को अपना उप सहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय (डब्ल्यूएचएमओ) का निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले वर्गीज बाइडन के चुनाव अभियान एवं शपथ ग्रहण समिति में भी अहम सदस्य के तौर पर काम कर चुके हैं। वर्गीज ने नियुक्ति की घोषणा के बाद व्हाइट हाउस के अराइवल लाउंज में खींची गई तस्वीर के साथ ट्वीट किया, ''माजू वर्गीज अब राष्ट्रपति के उप सहायक एवं व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय के निदेशक हैं।'' उन्होंने मंगलवार को तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ''प्राइमरी और आम चुनाव के बाद शपथग्रहण, इस यात्रा के लिए, शानदार टीम के लिए और हमने जो इतिहास बनाया, उसके लिए आभारी हूं। देश और राष्ट्रपति की सेवा कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं परिवार के साथ उन दरवाजों से दोबारा गुजर कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हैं, उनकी कहानी और उम्मीदें मेरे साथ है।'' उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूएचएमओ व्हाइट हाउस में ही एक कार्यालय है जो व्हाइट हाउस के कामकाज के लिए सैन्य मदद मुहैया कराता है जैसे कि खाद्य सेवा, राष्ट्रपति के लिए परिवहन, चिकित्सा एवं सत्कार सेवा। डब्ल्यूएचएमओ निदेशक अमेरिका के राष्ट्रपति की दुनिया भर में यात्रा के दौरान एयरफोर्स वन (राष्ट्रपति का आधिकारिक विमान) में सभी सैन्य परिचालन देखता है। उल्लेखनीय है कि वर्गीज का जन्म अमेरिका में ही हुआ है और उनके माता-पिता केरल के तिरुवला से यहां आए थे। उन्होंने मैसाच्युसेट्स विश्वविद्यालय से राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषय में स्नातक किया है।

भारत का 'मेक इन इंडिया' अभियान अमेरिका- भारत व्यापार संबंधों में चुनौती

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी संसद से कहा है कि भारत में हाल में शुरू किया गया 'मेक इन इंडिया'कार्यक्रम दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों में खड़ी होने वाली चुनौतियों का प्रतीक बन गया है। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने अपनी 2021 की व्यापार नीति एजेंडा और 2020 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि 2020 के दौरान अमेरिका ने लगातार भारत के साथ बाजार पहुंच से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिये प्रयास जारी रखा। यूएसटीआर की सोमवार को कांग्रेस को सौंपी गई इस रिपोर्ट में कहा गया है, ''भारत का बड़ा बाजार, आर्थिक वृद्धि और विकास की ओर अग्रसर उसकी अर्थव्यवस्था जहां उसे अमेरिकीनिर्यातकों के लिये आवश्यक बाजार बनाती है वहीं दूसरी तरफ भारत में सामान्य तौर पर व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाली नीतियों के चलते द्विपक्षीय व्यापार संभावनाओं को कम किया है।भारत में हाल में आयात के विकल्प के तौर पर शुरू किये गये 'मेक इन इंडिया' अभियान ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के समक्ष चुनौतियों को बढ़ा दिया है। अमेरिका ने 5 जून 2019 से सामन्यीकृत तरजीही प्रणाली (जीएसपी) कार्यक्रम के तहत भारत की पात्रता को समाप्त कर दिया था।

अमेरिका ने यह कदम जीएसपी बाजार पहुंच मानदंड के मामले में भारत के अनुपालन पात्रता को लेकर उठी चिंताओं की समीक्षा के बाद उठाया। जीएसपी के तहत भारत को मिलने वाले व्यापार लाभ निलंबित कर दिये जाने के बाद से ही अमेरिका और भारत 2019 से तार्किक बाजार पहुंच पैकेज पर काम करने में जुटे हुये हैं। वर्ष 2020 में भी यह काम जारी रहा। इस बातचीत में अमेरिका का उद्देश्य भारत में कई तरह की गैर- शुल्कीय बाधाओं को दूर करना, विभिन्न शुल्कों में लक्षित कमी लाना और भारत में अमेरिकी उत्पादों के लिये बाजार पहुंच में सुधार लाना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में अमेरिका में आयात की गई सेवाओं में 62.3 अरब डालर के साथ ब्रिटेन लगातार सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा। वहीं भारत 29.7 अरब डालर की सेवाओं के आयात के साथ छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा। कनाडा से 38.6 अरब डालर, जापान से 35.8 अरब डालर, जर्मनी से 34.9 अरब डालर और मैक्सिको से 29.8 अरब डालर की सेवाओं का आयात किया गया।

डब्ल्यूटीओ में कोविड-19 टीकों पर छूट को नहीं रोकने का अनुरोध, कोरोना मरीजों को होगा फायदा

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

भारत और दक्षिण अफ्रीका का समर्थन करते हुए अमेरिका के सैकड़ों सामाजिक संगठनों और तीन वरिष्ठ सांसदों ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से डब्ल्यूटीओ में कोविड-19 टीकों पर मिलने वाली छूट को नहीं रोकने का अनुरोध किया है और कहा है कि इस छूट से दुनियाभर में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज को बढ़ावा मिलेगा। बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं (टीआरआईपीएस) पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के समझौते के तहत देशों को दवाइयों, परीक्षणों और उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों के लिए दीर्घकालिक एकाधिकार सुरक्षा प्रदान करना जरूरी होता है। एक बयान में कहा गया है कि हर क्षेत्र में उत्पादन क्षमता होती है और डब्ल्यूटीओ के नियम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी फॉर्मूला और प्रौद्योगिकी तक समय रहते निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने से रोकते हैं। निर्माण अधिक मात्रा में नहीं होने से 2024 तक विकासशील देशों के कई लोगों को कोविड-19 टीका नहीं मिल पाएगा। प्रतिनिधि सभा में हाउस एप्रोप्रिएशंस कमेटी की अध्यक्ष एवं सांसद रोसा डेलॉरा ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''कोविड-19 महामारी किसी देश की सीमा तक सीमित नहीं है। ऐसे में दुनियाभर में टीके का निर्माण एवं वितरण बेहद अहम हो जाता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने डब्ल्यूटीओ से टीआरआईपीएस से छूट की मांग की है जिससे वैश्विक समुदाय को कोविड-19 के निदान, उपचार और टीकों को विकासशील देशों को उपलब्ध कराते हुए इस समस्या से निपटने की दिशा में मदद मिलेगी।'' सांसद अर्ल ब्लूमेनॉर और सांसद जैन शाकोवस्की ने भी राष्ट्रपति जो बाइडन से इस बारे में दखल देने का अनुरोध किया है।

क्या पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या में था सऊदी अरब के शहजादे का हाथ? संयुक्त राष्ट्र में उठे सवाल

संयुक्त राष्ट्र। (एजेंसी)।

संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब के राजदूत ने सोमवार को अमेरिका की उस खुफिया रिपोर्ट पर सवाल उठाए, जिसमें सऊदी अरब के शहजादे (क्राउन प्रिंस) द्वारा पत्रकार जमाल खशोगी को ''पकड़ने या मारने'' के एक अभियान को मंजूरी देने का दावा किया गया है। अब्दल्लाह अल-मौलिमी ने इस रिपोर्ट पर विरोध जताते हुए ट्वीट किया, '' हम सभी को दुनिया के गंभीर मुद्दों के समाधान के लिये आगे बढ़ना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि 'सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी' की नई रिपोर्ट '' हो सकता है, होना चाहिए तथा हुआ होगा पर आधारित है और संदेह के अलावा आरोप साबित करने में सक्षम नहीं है।'' रिपोर्ट में सऊदी अरब के शहजादे (क्राउन प्रिंस) मोहम्मद बिन सलमान का नाम लिये बगैर इशारों में कहा गया कि उन्होंने इस्तांबुल में पत्रकार जमाल खशोगी को ''पकड़ने या मारने'' के एक अभियान को मंजूरी दी थी। सऊदी अरब के असंतुष्ट पत्रकार की बर्बर हत्या से संबंधित यह रिपोर्ट अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने जारी की है।

रिपोर्ट खुफिया अधिकारियों ने हालांकि यह नहीं कहा कि शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने अक्टूबर 2018 में खशोगी की हत्या का आदेश दिया था, बल्कि उन्होंने चार पृष्ठ के दस्तावेज में कहा कि शहजादे का देश की सुरक्षा एवं खुफिया संगठनों पर पूर्ण नियंत्रण है। इस बात की संभावना नहीं है कि सऊदी अधिकारी इस प्रकृति का अभियान बिना शहजादे की इजाजत के चलाएं। उन्होंने कहा, '' यदि यह एक वैध तर्क है कि अबू गरीब अपराधों के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं थे?'' अल-मौलिमी का इशारा इराकी जेल की 2004 में सामने आई उन तस्वीरों से था, जिनमें अमेरिकी सैनिक कैदियों पर अत्याचार करते नजर आ रहे थे। अल-मौलिमी ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, '' शहजादे ने साहसपूर्वक नैतिक जिम्मेदारी ली, आरोपी को न्याय के दायरे में लेकर आए और खुफिया संगठनों को सुधारने का संकल्प व्यक्त किया। मामला बंद।'' गौरतलब है कि खशोगी की दो अक्टूबर 2018 को तुर्की के इस्तांबुल शहर में सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास में मोहम्मद बिन सलमान से संबंधित लोगों ने हत्या कर दी थी। वह अमेरिका के वैध स्थायी निवासी थे और वाशिंगटन पोस्ट अखबार में लेख लिखते थे और शहजादे की नीतियों के कटु आलोचक थे। खशोगी के शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए गए थे और उनके अवशेष कभी नहीं मिले। सऊदी अरब को आखिरकार मानना पड़ा कि खशोगी की हत्या गलती से हुई थी हालांकि हत्याकांड में शहजादे की संलिप्तता से इनकार किया था।

अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्री ने ट्रंप पर लगाया आरोप, कहा- पूर्व राष्ट्रपति ने आव्रजन प्रणाली को किया ध्वस्त

वाशिंगटन। अमेरिका के गृह सुरक्षा मंत्री एलेजांद्रो मायोरकास ने सोमवार को आरोप लगाया कि देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी आव्रजन प्रणाली को ध्वस्त कर दिया और इसे ''नए सिरे से पुनः बनाने में'' समय लगेगा। पूर्ववर्ती ट्रंप सरकार ने अमेरिका में शरण मांगने वालों के लिए आव्रजन नियम कड़े कर दिए थे और अमेरिकी कर्मियों की रक्षा के लिए योग्यता के आधार पर आव्रजन प्रणाली की वकालत की थी। मायोरकास ने व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''हम पूर्ववर्ती प्रशासन की निर्दयता को एक व्यवस्थित, मानवीय एवं सुरक्षित आव्रजन प्रणाली के जरिए बदलने के लिए चौबीस घंटे काम कर रहे हैं और हम इसे हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह मुश्किल है और इसमें समय लगेगा, लेकिन इस बात का भरोसा है कि हम यह कर लेंगे।'' गृह सुरक्षा मंत्री ने संसद में पारित मानवीय कानूनों को लागू करने में पर्याप्त सुविधाओं के ''अभाव'' की बात की। उन्होंने कहा, ''पूरी प्रणालियां एक दिन या कुछ सप्ताह में नहीं बन जातीं। संक्षेप में कहें, तो पूर्ववर्ती प्रशासन ने हमारे देश की आव्रजन प्रणाली को पूरी तरह नष्ट कर दिया। जब मैंने 27 दिन पहले पदभार संभाला, तो पाया कि हमारे पास संसद में वर्षों पहले पारित मानवतावादी कानूनों को लागू करने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं।

ग्रे सूची से खुद को निकालेगा पाकिस्तान, क्या एफएटीएफ की तीनों बिंदुओं को कर सकेगा पूरा?

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर धन शोधन एवं आतंकवादियों के वित्त पोषण पर नजर रखने वाले वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की 27 बिंदुओं वाली कार्य योजना के तीन बचे हुए मापदंडों को जून की नई समयसीमा समाप्त होने से पहले पूरा करने के लिए एक और विधेयक की आवश्यकता होगी। एक मीडिया रिपोर्ट में मंगलवार को यह बात कही गई। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे सूची में डाल दिया था और उससे 2019 के अंत तक धनधोशन एवं आतंकवादियों को वित्त पोषण रोकने के लिए कार्य योजना लागू करने को कहा था, लेकिन कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया था। एफएटीएफ ने पिछले महीने नई समय सीमा तय की थी। पाकिस्तान धनशोधन एवं आतंकवाद को वित्त पोषण रोधी एफएटीएफ के नियमों का पालन नहीं करने वाले देशों की सूची में डाले जाने से बचने के लिए हालिया कुछ महीनों से काफी कोशिश कर रहा है। यदि पाकिस्तान को इस सूची में डाल दिया जाता है, तो पहले ही कमजोर उसकी अर्थव्यवस्था को और नुकसान होने की आशंका है। 'डॉन' समाचार पत्र ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान सरकार को बची हुई चिंताओं से निपटने के लिए विधेयक बनाने और अन्य कदमों में प्रगति को लेकर एफएटीएफ को एक महीने के भीतर अद्यतन रिपोर्ट भेजनी होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने एफएटीएफ की अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए पिछले एक साल से अधिक समय में करीब तीन दर्जन कानूनों में बदलाव किया है, ऐसे में अतिरिक्त विधेयक लाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।

पाकिस्तान के वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख ने धनशोधन रोधी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एफएटीएफ समन्वय समिति के अध्यक्ष और उद्योग एवं उत्पादन मंत्री हम्माद अजहर और वित्तीय निगरानी इकाई (एमएमयू) से संघीय सरकार की एजेंसियों एवं सशस्त्र बलों के साथ विचार-विमर्श करके अतिरिक्त विधेयक के लिए तत्काल समय सीमा तय करने को कहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान ने पिछले दो साल में काफी प्रगति की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी तारीफ की है, लेकिन बार-बार अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं हो पाने और समय सीमा के भीतर काम नहीं हो पाने के कारण गलत संदेश जाता है। एनईसी को सूचित किया गया कि पाकिस्तान को एफएटीएफ को 30 दिन के भीतर बताना होगा कि वह एफएटीएफ द्वारा रेखांकित की गई अपनी कमियों को किस समय सीमा में पूरा करेगा और उसकी आगे की क्या योजना है।

रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को एक अतिरिक्त विधेयक बनाना होगा, जिनमें मौजूदा ढांचे की उन कुछ कमजोरियों को दूर किया जाए, जो आतंकवादी संगठनों के लिए काम कर रहे लोगों को पकड़ने या उन पर प्रतिबंध लगाने समेत उनके खिलाफ कदम उठाने और

उन पर मुकदमा चलाने की प्राधिकारियों की शक्तियों को सीमित करती हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान को तीन शेष बिंदुओं पर काम करना हैं। उसे यह दिखाना होगा कि प्रतिबंधित व्यक्तियों एवं संगठनों के लिए काम करने वाले लोगों एवं संगठनों को निशाना बनाकर आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी जांच की गई और अभियोग चलाए गए। इसके अलावा पाकिस्तान को यह दिखाना होगा कि इन अभियोगों के कारण प्रभावशाली और पर्याप्त प्रतिबंध लगाए गए। पाकिस्तान को यह भी दिखाना होगा कि उसने सभी प्रतिबंधित आतंवादियों के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंधों का प्रभावशाली क्रियान्वयन किया। सूत्रों ने बताया कि बैठक में बताया गया कि तीन में से एक बिंदू पर काफी काम कर लिया गया है,लेकिन जिन दो बिंदुओं को दिखाने के लिए अतिरिक्त विधेयक की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों में लक्ष्य हासिल करने में समय लगेगा।

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

चुनाव सांप्रदायिक वोटों की जागीरदारी और समावेशी विकास की भागीदारी के बीच जनादेश की जंग है: नकवी

नयी दिल्ली। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा के चुनाव 'सांप्रदायिक वोटों की जागीरदारी' और 'समावेशी विकास की भागीदारी' के बीच जनादेश की जंग है। नकवी के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि इन चुनावों में विकास पर विश्वास एक 'बड़ी कसौटी' है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विकास और सुशासन का 'प्रामाणिक ब्रांड' बताते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तीकरण के संकल्प के जरिये हर जरूरतमंद तक विकास की रौशनी पहुंचाने का प्रयास किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नकवी ने कहा कि कुछ राजनैतिक दल विरासत पर सियासत को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ही लोग कर्म की कसौटी पर असफल हो रहे हैं।

किसानों के लागातार प्रदर्शन के कारण दिल्ली पुलिस ने फिर किया गाजीपुर बॉर्डर बंद

नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार दोपहर को गाज़ीपुर बॉर्डर को फिर बंद कर दिया। इससे कुछ घंटों पहले एनएच-9 का एक हिस्सा गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था। यह रास्ता 26 जनवरी से ही बंद है जब गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हिंसा भड़क गई थी। सुबह में सड़क का एक हिस्सा खोल दिया था जो दिल्ली से गाज़ियाबाद की ओर जाता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पिछले साल नवंबर के अंत से प्रदर्शन कर रहे हैं।

उत्तराखंड विधानसभा में चमोली आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई

गैरसैंण। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को पिछले महीने चमोली जिले में आई प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने चमोली जिले की जोशीमठ तहसील के रैंणी और तपोवन क्षेत्र में आपदा में मरे लोगों के लिए शोक व्यक्त किया। सदन ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कुछ पल का मौन भी रखा। गौरतलब है कि सात फरवरी को ऋषिगंगा घाटी में आई विकराल बाढ में जानमाल की भारी क्षति हुई थी। इस हादसे में 204 लोग लापता हो गए थे जिसमें से अब तक 72 लोगों के शव मिले हैं। आपदा में 13.2 मेगावाट रैंणी जलविद्युत परियोजना पूरी तरह से तबाह हो गई जबकि 520 मेगावाट तपोवन–विष्णुगाड जलविद्युत परियोजना को भारी नुकसान हुआ।

दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आठ मार्च से शुरू होगा, मनीष सिसोदिया ने दी सूचना

नयी दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आठ मार्च से शुरू होगा। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया। सत्र का समापन 16 मार्च को होगा। सूत्रों के अनुसार सरकार 2021-22 के लिए अपना बजट पेश करेगी जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी की आपूर्ति समेत बुनियादी ढांचा पर जोर रहेगा। सूत्रों ने बताया कि नए कर लगाने की संभावना नहीं है। सरकार ने 2020-21 के लिए 65,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था जो 2019-20 के लिए पेश बजट से करीब 10 प्रतिशत अधिक था।

ममता के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम हमले की एनआईए जांच होगी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) करेगी। मर्शीदाबाद में रेलवे स्टेशन जाते वक्त 17 फरवरी को जाकिर हुसैन पर बम से हमला किया गया था। वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। ईलाज के लिए उन्हें कोलकाता में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले के लिए एसआईटी जांच का आदेश दिया था। साथ ही जाकिर हुसैन पर हुए बम हमले के लिए केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा था। मुर्शिदाबाद के निमिता रेलवे स्टेशन पर यह हमला हुआ था। पश्चिम बंगाल के श्रम राज्यमंत्री प्लेटफार्म नंबर 2 पर कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। इस बम हादसे का वीडियो भी सामने आया था। इस मामले में राजकीय रेलवे पुलिस ने हत्या के प्रयास. आपराधिक पडयंत्र और विस्फोटक अधिनियम समेत कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई है जिसके बाद आला अधिकारी इस मामले में अब तक की जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आए हैं उन सभी को ध्यान में रखकर आगे की जांच और पूछताछ की जाएगी।

किसान नेताओं पर बरसे जेपी नड्डा, बोले- ये कृषि सुधार किसान की तस्वीर व तकदीर बदलेंगे

जयपुर। (एजेंसी)।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नये कृषि कानूनों की ओर इशारा करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि कृषि सुधार देश के किसानों की तस्वीर व तकदीर बदलने वाले हैं। इसके साथ ही नड्डा ने किसान नेताओं पर आरोप लगाया कि सालों साल तक उन्होंने किसानों के नाम पर राजनीति की है उनका भला नहीं किया। नड्डा यहां बिड़ला सभागार में भाजपा की राजस्थान प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने वर्षों तक किसानों पर राजनीति की लेकिन उनका भला नहीं किया। अगर किसान का भला किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आदि का जिक्र करते हुए कहा, ''ये सुधार किसान की तस्वीर व तकदीर बदल देंगे इस बात की गारंटी है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने कहा हम आपके साथ बातचीत को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह वैकल्पिक हैं अगर अपनान चाहें तों अपनाएं।'' भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ''हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं आप इसमें बताएं की क्या सुधार करने

की जरूरत है हम करेंगे... किसान हमारे अन्नदाता हैं उनको मुख्यधारा में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है लेकिन यह जो पार्टियां राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक रोटियां सेंकने का काम कर रही हैं और लोगों को गुमराह कर रही हैं, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि गांव-गांव घर-घर जाकर प्रत्येक किसान को बताएं कि सुधारों से उनका भला कैसे होगा।'' उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एपीएमसी को समाप्त करने की बात उनके चुनावी घोषणापत्र में थी। उन्होंने कहा, ''पंजाब में ठेका खेती नहीं है क्या? कांट्रेक्ट खेती का कानून पंजाब की कांग्रेस सरकार लेकर नहीं आई थी? ... तुम करो तो सच हम करें तो झूठ।'' नड्डा ने बेरोजगारी, दलित व महिलाओं पर अत्याचार व किसान कर्जमाफी को लेकर राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले सत्ता पाने के लिए इतने फस्ट्रेशन में हैं कि कुछ भी वादा करेंगे और जो भी वादा करेंगे उसे कभी निभाएंगे नहीं। उन्होंने कहा, ''मेरा आरोप है कि राज्य की मौजूदा गहलोत सरकार की प्राथमिकता सुशासन देना की नहीं बल्कि इसे कुशासित राज्य बनाने की है।'' नड्डा ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि राजस्थान में कमल पहले भी खिला है और आगे भी खिलेगा। इससे पहले सुबह जयपुर पहुंचने पर पार्टी के राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व अर्जुनराम मेघवाल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। मंच पर राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व अर्जुनराम मेघवाल, राज्यसभा सदस्य ओम माथुर भी एक साथ दिखे।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर एसपी का बहिर्गमन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने बहिर्गमन किया और सरकार की आलोचना की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने दावा किया कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि मूल्य वृद्धि का प्रभाव गरीबों पर ना पड़े। शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा, रसोई गैस की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है और लोगों को सब्सिडी भी कम मिल रही है। दस माह से कम समय में बलिया गैस सिलेंडर की कीमत में 240 रुपये से अधिक वृद्धि हुई है।'' उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों भी लगभग हर रोज वृद्धि हो रही है और यह किसानों और आम जनता को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी होने के कारण बस, आटो रिक्शा के किराये और दाल, खाद्य वस्तुओं और दवाओं के दाम में भी वृद्धि हुई है। चौधरी ने सवाल उठाया कि यह सरकार जनकल्याणकारी सरकार कैसे हो सकती है, क्या सरकार का मतलब कीमतों को बढ़ाना और लोगों को आत्महत्या के लिए मजबूर करना है। उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीबों के हित के लिए नहीं है और सभी मोर्चों पर विफल रही है।

चौधरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार द्वारा नियंत्रित होती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अंत्योदय के सिद्धांत पर आखिरी आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खड़ी है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। खन्ना ने दावा किया कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि मूल्य वृद्धि का प्रभाव गरीबों पर ना पड़े।

केरल का सामाजिक सौहार्द दबाव में, नई विकास रणनीति की जरूरत : सोनिया गांधी

तिरुवनंतपुरम। (एजेंसी)।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को कहा कि केरल का समाजिक सद्भाव व सौहार्द दबावमें हैं। उन्होंने लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ाने और दक्षिणी राज्य के समूचे विकास के लिये नई विकास रणनीति की वकालत की। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज (आरजीआईडीएस) द्वारा आयोजित एक डिजिटल शिखर सम्मेलन में अपने संदेश में गांधी ने कहा, 'केरल देश के अन्य हिस्सों और कहें तो दुनिया को यह सबक देता है कि कैसे सामाजिक सद्भाव व सौहार्द का संरक्षण और संवर्धन करें।' उन्होंने कहा, 'यह दबाव व तनाव में है और भविष्य की विकास की रणनीति में भाइचारे के बंधन को मजबूती दी जानी चाहिए। यह न केवल इसके मूल उद्देश्यों में से एक हैं, बल्कि केरल के अद्भुत विविध समाज की पहचान रहा है।'

आरजीआईडीएस केरल में कांग्रेस की विचारधारा से संबद्ध एक आर्थिक 'थिंक-टैंक' है। शिखर सम्मेलन, प्रतीक्षा 2030, अगले दशक में केरल के विकास की व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के लिये भारत और विदेश में आरजीआईडीएस के विस्तृत और व्यापक परामर्श

की परिणति है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। विकास के बहुचर्चित केरल मॉडल के संदर्भ में गांधी ने कहा कि राज्य आज नई व अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है और इन्हें कोविड-19 महामारी से और बल मिला है। उन्होंने दक्षिणी राज्य में आर्थिक सुधार और सामाजिक सुरक्षा के लिये नई सोच की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन में पढ़े गए संदेश में उन्होंने कहा, 'यह आर्थिक वृद्धि के लिये स्पष्ट रूप से नई सोच का समय है जिससे फिर से निवेश हो, उत्पादक रोजगार का सृजन हो, पर्यावरण का संरक्षण हो, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला रुख हो, प्राकृतिक आपदाओं के खतरों को कम करे, संगठित व असंगठित श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा बढ़े, किसानों व उनके परिवारों की कुशलता बढ़े।'

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बीते छह दशकों से भी ज्यादा समय में विकास के केरल मॉडल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, लैंगिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में राज्य के लिये कई प्रभावी उपलब्धियां अर्जित की हैं। लेकिन केरल के सामने नई चुनौतियां हैं और मैं कह सकती हूं कि अभूतपूर्व चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा, 'इन चुनौतियों को कोविड-19 महामारी से और बल मिला जिसका सामना पूरी दुनिया कर रही है और यह खतरा अभी कायम है।' शिखर सम्मेलन की सराहना करते हुए गांधी ने कहा कि इन परामर्श के फलस्वरूप दृष्टिपत्र तैयार हुआ जिसे आज जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'वास्तव में यह सिर्फ दृष्टिपत्र नहीं, यह मिशन पत्र भी है जो राज्य के लोगों की अकांक्षाओं को पूरा करने के लिये विस्तृत खाका पेश करता है।' उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला और निदेशक बी एस शिजू के नेतृत्व वाले आरजीआईडीएस के दल को भी इस पहल के लिये बधाई दी। उन्होंने कहा, 'मैं सिर्फ इतना ही और कहना चाहूंगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राज्य के लोगों का भरोसा और विश्वास जीत कर जल्द ही विजन/मिशन दस्तावेज का अक्षरशः क्रियान्वयन शूरू करेगी।

तृणमूल की तुष्टिकरण, वोटबैंक की राजनीति ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला: योगी

मालदा (पश्चिम बंगाल)। (एजेंसी)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की अपनी समकक्ष ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए उन पर तुष्टिकरण की राजनीति करने और वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध प्रवासियों को राज्य में आने की अनुमति देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। आदित्यनाथ ने वादा किया कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो गो तस्करी को एक दिन के भीतर रोक दिया जाएगा। मालदा जिले के गज़ोले में एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा नेता ने दावा किया कि कभी देश की अगुवाई करने वाला पश्चिम बंगाल अराजक स्थिति का सामना कर रहा है। आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि राज्य में लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं लेकिन तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार उन्हें रोकने में नाकाम रही है। आदित्यनाथ ने कहा, वोट बैंक की खातिर तुष्टीकरण की राजनीति ने न केवल पश्चिम बंगाल, बल्कि देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। टीएमसी सरकार को शरणार्थियों को नागरिकता मिलने से समस्या है, लेकिन राज्य में अवैध प्रवासियों के आने से कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में जय श्रीराम का नारे लगाने की अनुमित नहीं है। राज्य के लोग उनकी धार्मिक भावनाओं से खेलने के लिए टीएमसी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाने की अनुमति नहीं है, लेकिन लोग इसे जारी नहीं रखेंगे। बंगाल में लव जिहाद' की घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में, हमने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक कानून बनाया है लेकिन टीएमसी सरकार गाय की तस्करी और लव जिहाद ,दोनों को रोकने में विफल रही है। उन्होंने कहा, अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है तो हम 24 घंटे में गाय की तस्करी रोकेंगे। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्य विधानसभा के लिए 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच आठ चरणों में चुनाव होने हैं।

असम की जनता को प्रियंका गांधी ने दी पांच गारंटी, कहा- कांग्रेस की सरकार बनाएं और लाभ उठाएं

गुवाहाटी। (एजेंसी)।

असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तेजपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम खोखले वादे नहीं करने आए हैं। कुछ समय से असम में कांग्रेस के नेता भ्रमण कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने जो बातें सुनी है उसके मुताबिक उन्होंने तय किया है कि असम की जनता को पांच गारंटी देंगे।

पहली गारंटी- कांग्रेस अगर असम में सत्ता में आई तो संशोधित नागरिकता कानून को निरस्त करने के लिए नया कानून लेकर आएगी।

दूसरी गारंटी- अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिजली की 200 यूनिट आप लोगों को मुफ्त में मिलेंगे। बिजली के बिल से आपके 1400 रुपये हर महीने बच जाएंगे।

तीसरी गारंटी- गृहिणी सम्मान योजना दी जाएगी। इसके तहत घर संभालने वाली महिलाओं को 2000 रुपए महीना दिया जाएगा।

चौथी गारंटी- चाय बागानों में काम करने वालों की न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाई जाएगी। उन्हें 365 रुपए का वेतन दिया जाएगा।

पांचवी गारंटी- कांग्रेस पार्टी की असम में सरकार बनेगी तो कम से कम 5 लाख सरकारी नौकरियां देगी।

उन्होंने कहा कि हमारी एक पूरी टीम असम की अर्थव्यवस्था और आंकड़ों को देखकर एक योजना तैयार की है। जिसके तहत हमने आपको यह गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि यहां की समस्याओं को सुनकर, बेरोजगारी को देखकर बहुत दुख होता है। यहां के नेता बड़े-बड़े नेता चार्टर प्लेन में घूमते हैं। आज कल चीनी और जापानी ग्रीन टी भी पीने लगे हैं। शायद उन्हें यहां की कड़क चाय पिलानी पड़ेगी और उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि उनकी जगह क्या है।

किसान आंदोलन: फड़णवीस ने हस्तियों के ट्वीट का मुद्दा उठाया, देशमुख ने किया बचाव

मुंबई। (एजेंसी)।

भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को दिल्ली के नजदीक किसानों के आंदोलन को लेकर कुछ विदेशी हस्तियों के ट्वीट के बाद भारत के समर्थन में सचिन तेंदुलकर एवं लता मंगेशकर की ओर से किए गए ट्वीट की कथित जांच कराने को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने हालांकि इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने भाजपा के आईटी प्रकोष्ठ के ट्वीट की जांच करने के आदेश दिए थे न कि क्रिकेटर तेंदुलकर और गायिका लता मंगेशकर द्वारा किए गए ट्वीट की।

उल्लेखनीय है कि देशमुख ने कहा था कि राज्य का खुफिया विभाग इस बात की जांच करेगा कि किसान आंदोलन को लेकर कुछ हस्तियों ने दबाव में तो ट्वीट नहीं किया। तेंदुलकर एवं मंगेशकर सहित कई प्रमुख हस्तियों ने केंद्र सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर चलाए हैशटैग भारत एकजुट है एवं भारत प्रोपगेंडा के खिलाफ है के साथ ट्वीट किया था। फडणवीस ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में कहा कि तेंदुलकर और मंगेशकर

ने 'भारत प्रोपगेंड के खिलाफ है' और 'भारत एकजुट'' है ट्वीट किया था। उन्होंने कहा, 'क्या इस देश में भारत एकजुट कहना गलत है कोई खड़ा होता है और गृहमंत्री से शिकायत करता है।'' फडणवीस ने कहा कि देशमुख ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने से पहले सोचें। देशमुख ने हालांकि फडणवीस के आरोपों से इनकार कर दिया। मंत्री ने कहा, 'मैंने तेंदुलकर या मंगेशकर की जांच कराने की बात नहीं की थी। मैंने राजनीतिक पार्टी के आईटी प्रकोष्ठ की जांच कराने की बात कही थी जिसका नाम मैं नहीं ले रहा।' उन्होंने कहा, 'जांच में 12 लोगों का नाम आया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।' बाद में देशमुख ने कहा कि यह भाजपा का आईटी प्रकोष्ठ है।

इतिहास में पहली बार नागपुर से बाहर होगी संघ की चुनावी बैठक, जानिए वजह

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बेंगलुरु में होनी है। यह बैठक 19 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच होगी। हालांकि, संघ की यह बैठक हर साल होती है लेकिन इस साल की यह बैठक कुछ खास है। दरअसल, इस साल संघ की चुनावी बैठक है। साथ ही साथ यह बैठक पहली बार नागपुर से बाहर आयोजित की जा रही है। संघ में हर 3 साल बाद सरकार्यवाह का चुनाव होता है। करीब एक दशक पहले तक संघ की इस सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक नागपुर में ही की जाती रही है। लेकिन बाद में यह तय किया गया कि अब हर तीसरी बैठक नागपुर में होगी, बाकी की दो बैठक अलग-अलग हिस्सों में की जाएगी। इस साल भी यह बैठक नागपुर में ही होनी थी।

लेकिन, अब यह बैठक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होगी। संघ के एक पदाधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग नियम है। महाराष्ट्र में वर्तमान में कोरोना वायरस प्रकोप को ध्यान में रखते हुए यह बैठक नागपुर के बाहर कराने का फैसला लिया गया। नागपुर में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि अब यह बैठक नागपुर की बजाय बेंगलुरु में की जा रही है। पदाधिकारी ने बताया कि हर तीसरे साल होने वाली बैठक में जिला संघचालक, प्रांत संघचालक विभाग, संघ चालक सहित सरकार्यवाह का चुनाव कराया जाता है। आपको बता दें कि संघ में सबसे बड़ा कार्यकारी पद सरकार्यवाह का ही होता है।

वर्तमान की बात करें तो भैया जी जोशी एक दशक से भी ज्यादा समय से संघ के सरकार्यवाह हैं। इस बार भी चर्चा इस बात की है कि शायद संघ को कोई नया सरकार्यवाहक मिल जाए। हालांकि, 3 साल पहले भी इसी तरह की कुछ चर्चा थी। लेकिन आखिर में भैया जी जोशी ही चुने गए। एक बात और है कि संघ के इतिहास में कभी चुनाव की नौबत नहीं आई है। अब तक हर बार सरकार्यवाह का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ है। चुनावी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाता है। सर कार्यवाहक के लिए नाम भी आमंत्रित किए जाते हैं। लेकिन फिर भी कभी वोटिंग की नौबत नहीं आई। चुनाव के बाद सरकार्यवाहक अपनी नई टीम का एलान करते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार प्रतिनिधि सभा की संख्या में कमी की जा सकती है। संघ की इस बैठक में देश के भी कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ पांच चुनावी राज्यों पर भी संघ की निगाहें रहेंगी।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)